

SCG न्यूज

लाईफ वर्सिटी

वर्ष- 03

अंक -09

फरवरी 2026

मूल्य - 50 रु.

Postal Regn. No. C.G./RYP/DN/108/2024-26 RNI No. CHHHINI/2023/87466

जन-जंगल-गणतंत्र



www.phzinfo.com

Positive Health Zone

Integrated Holistic
Health Care System

Unique Wellbeing Center



Holistic Healthcare Team

Our INTEGRATED SERVICES

Holistic Path Of Wellness & Wellbeing



MIND BRAIN BODY SOUL
M.B.B.S

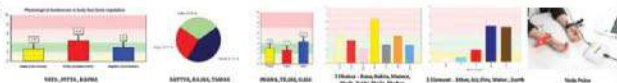
- 1 Personal Energy Blueprint at Quantum Veda Lab with Latest Quantum Devices-

Aura, Chakra, Biofield,
Lifeforce Energy Analysis.



- 2 Digital Nadi Parikshan Modern Nadi Veda Pulse -

Personality Analysis
Body Type, Mind
Type, Energy Type.



- 3 Life Style Clinic

Personalised Diet Plan, Lifestyle
Plan, Day Plan, Detox Plan as
per your Quantum Analysis.



- 4 Body Detox & Rejuvenation with
Kerala Ayurveda Panchkarma.



- 5 Mind Detox & Stress Management
with NLP & Counselling.



- 6 Inner Alingment, Chakra Balancing
with PNP Meditation.



Get In Touch

9109185026, 9109185025



A-41, Amrapali Society,

Near. Ganga Diagnostics, Raipur, Chhattisgarh



www.phzinfo.com

सम्पादक

नरेन्द्र कुमार पाण्डेय



प्रबंधक

हर्षित पाण्डेय



सलाहकार मण्डल

डॉ अनिल गुप्ता रायपुर
डॉ उदयभान सिंह चौहान रायपुर
प्रो. डॉ शुभा सान्याल नई दिल्ली
प्रो तपन मोहनित ओड़िसा



सलाहकार (मीडिया मार्केटिंग एंड एआई)

भूपेन्द्र सिंग



छत्तीसगढ़ कार्यालय

ए-32, आम्रपाली सोसाइटी, कलर्स
मॉल के पीछे, पचपेड़ी नाका
रायपुर (छ.ग.)
मो. 88171-94979



मध्यप्रदेश कार्यालय

अनामिका पाण्डेय

गोकुलधाम वेलोहान टोला,
सामान, रीवा मप्र



प्रतिनिधि

अम्बुज अग्निहोत्री जबलपुर
संजीव पाण्डेय भोपाल
राजेश सिंह बिलासपुर



कानूनी सलाहकार

संजयेंदु पंड्या



परिकल्पना

रजनीकांत पाण्डेय

अंदर के पृष्ठों पर



03

जन - जंगल - गणतंत्र



परेड सिर्फ दिखावा नहीं, संदेश बन जाती है



9

संस्कृति, सुरक्षा और विकास के त्रिकोण में छत्तीसगढ़



16

जहाँ शब्दों ने शहर से दिल तक का सफर तय किया



दवा में ज़हर-मंत्रि मीन

18

नंबरों से आगे, बच्चों के भविष्य की असली कहानी



23

- छत्तीसगढ़ के विकास का संयुक्त सूत्र 11
- सुशासन से समृद्धि की ओर छत्तीसगढ़ 13
- तिरंगा, वक्फ और मुस्लिम समाज 20
- स्तन कैंसर से जंग 24
- फाल्गुन में प्रेम 26
- आध्यात्म के दरबार में हैसियत 27



लाईफ वर्सिटी के प्रचार-प्रसार में सहयोग करें।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा बुरहानी प्रिंटर्स, सली बाजार रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं 6, विकास विहार कालोनी, साईं वाटिका, जेरातालाब के पास रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 88171-94979

E-mail : scgnewsraipur@gmail.com | www.scgnews.in



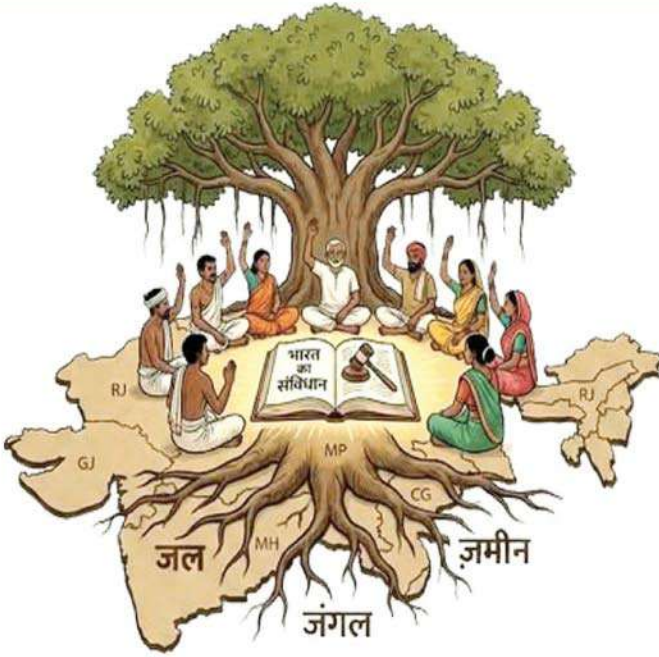
नरेन्द्र कुमार पाण्डेय
सम्पादक

राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश तक घटनाओं की रफ़्तार तेज है। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ नियम 94सी के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर संसद की गरिमा और निष्पक्षता पर बहस छेड़ दी है। 118 सांसदों के हस्ताक्षर इस बात का संकेत हैं कि विपक्ष टकराव की रणनीति से पीछे नहीं हटेगा। इतिहास में यह तीसरा अवसर है जब स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आया है। अब निगाहें इस पर हैं कि परीक्षण प्रक्रिया के बाद सदन का गणित क्या मोड़ लेता है।

छत्तीसगढ़ में दूसरी तस्वीर उभरती है। विष्णु देव साय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 6,414 जोड़ों का सामूहिक विवाह सामाजिक समावेशन का संदेश देता है। 2005 में शुरू हुई योजना में सहायता राशि 5 हजार से बढ़कर 50 हजार रुपये होना सामाजिक सुरक्षा के विस्तार का संकेत है। दंतेवाड़ा में पूर्व नक्सल प्रभाव क्षेत्र के युवाओं का मुख्यधारा में लौटकर विवाह करना बदलाव की सकारात्मक कहानी कहता है।

वहीं, राजनीतिक तापमान भी कम नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस नेताओं पर 500 करोड़ रुपये का मानहानि दावा लेका है। आरोप-प्रत्यारोप की यह लड़ाई अदालत तक पहुंच चुकी है।

सांस्कृतिक मोर्चे पर मैनपाट महोत्सव और अरपा महोत्सव जैसे आयोजन विकास और पर्यटन को नई पहचान दे रहे हैं। स्पष्ट है—राजनीति में संघर्ष जारी है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर राज्य आगे बढ़ने का संदेश भी दे रहा है।



जन - जंगल - गणतंत्र

नरेन्द्र पाण्डेय

77वां गणतंत्र दिवस बीत चुका है राजधानी की सड़कों से परेड गुजर गई। टैंक लौट गए, झांकियां अपने गोदामों में चली गईं और राष्ट्रगान की गूज अब सिर्फ स्मृतियों में रह गई है। लेकिन हर गणतंत्र दिवस की तरह इस बार भी एक सवाल पीछे छूट गया — क्या यह गणतंत्र अब भी जनता की जमीन पर खड़ा है? संविधान ने 26 जनवरी 1950 को यह घोषणा की थी कि भारत में सत्ता का स्रोत जनता होगी। जमीन, जंगल, जल और संसाधन जनता की साझी धरोहर होंगे। सरकार केवल संरक्षक होगी, मालिक नहीं। लेकिन 77 वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो तस्वीर थोड़ी धुंधली दिखती है। ऐसा लगता है जैसे गणतंत्र की जड़ें धीरे-धीरे जमीन से कट रही हैं। विकास के नाम पर जमीनों अधिग्रहित हो रही हैं। जंगल खनन कंपनियों को सौंपे जा रहे हैं। नदियों के किनारे निजी परियोजनाओं के लिए घिर रहे हैं। और

सार्वजनिक स्थान या तो धार्मिक ढांचों में बदल रहे हैं या व्यावसायिक परिसरों में।

यह लेख किसी एक सरकार, किसी एक विचारधारा या किसी एक प्रदेश की आलोचना नहीं है। यह उस व्यापक प्रवृत्ति का अध्ययन है जिसमें लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव — जनता की साझा संपत्ति धीरे-धीरे सिकुड़ती जा रही है। भारत में जमीन कभी सिर्फ जमीन नहीं रही। यह पहचान है, यह संस्कृति है, यह संघर्ष है, और यह सत्ता का सबसे बड़ा स्रोत भी है।

अगर किसी देश की राजनीति को समझना हो, तो उसकी संसद नहीं, उसकी जमीन की कहानी पढ़नी चाहिए। क्योंकि जहाँ जमीन का नियंत्रण बदलता है, वहीं समाज का चरित्र बदल जाता है। 1950 का दशक भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। देश जर्मंदारों उन्मूलन के दौर से गुजर रहा था। कानून बन रहे थे, सत्ता संरचनाएँ बदल रही थीं, लेकिन उसी समय एक संत सत्ता और कानून के बाहर खड़ा होकर नैतिक क्रांति की बात कर रहा था—विनोबा

66

77 वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो तस्वीर थोड़ी धुंधली दिखती है। ऐसा लगता है जैसे गणतंत्र की जड़ें धीरे-धीरे जमीन से कट रही हैं। विकास के नाम पर जमीनें अधिग्रहित हो रही हैं। जंगल खनन कंपनियों को सौंपे जा रहे हैं। नदियों के किनारे निजी परियोजनाओं के लिए घिर रहे हैं और सार्वजनिक स्थान या तो धार्मिक ढांचों में बदल रहे हैं या व्यावसायिक परिसरों में।

”

भावे।

उन्होंने जर्मंदारों से कहा था—'जिस जमीन पर किसान खेती कर रहा है, वह जमीन उसी को दान कर दीजिए।' यह भूदान आंदोलन था—नैतिकता के सहारे सामाजिक न्याय का प्रयोग लेकिन सात दशक बाद भारत उस नैतिक राजनीति से काफी दूर खड़ा दिखाई देता है। आज जमीन अदालतों, सरकारी फाइलों और कॉर्पोरेट सौंदों के बीच फँस गई है।

साझी धरोहर बनाम निजी नियंत्रण

1892 में अमेरिका की एक अदालत ने एक ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था— यदि कोई प्राकृतिक संसाधन जनता के सामूहिक उपयोग में है, तो सरकार उसे निजी संपत्ति में नहीं बदल सकती। इस सिद्धांत ने एक नई अवधारणा दी—सरकार मालिक नहीं होती, सरकार केवल ट्रस्टी होती है। भारत में भी इस सोच की झलक 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में दिखाई दी। इस कानून ने पहली बार यह स्पष्ट किया कि—

- जमीन अधिग्रहण से पहले जनता की सहमति जरूरी होगी
 - पुनर्वास और मुआवजा अनिवार्य होगा
- लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है—कानून बनाना

आसान होता है, उसे लागू करना सबसे कठिन। आज उद्योगों को बड़े भूखंड दिए जा रहे हैं। मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को भीविशाल भूमि आवंटित की जा रही है। यहाँ एक खतरनाक मानसिकता धीरे-धीरे विकसित होती दिखाई देती है—या तो जमीन भगवान की है, या सरकार की। जबकि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत कहता है—जमीन जनता की साझी धरोहर है।

अतिक्रमण का लोकतंत्र



विडंबना यह भी है कि भूमि संकट केवल बड़े कॉर्पोरेट सौदों तक सीमित नहीं है। यह आम समाज की मानसिकता में भी दिखाई देता है। सड़क किनारे खोमचा लगाने वाला धीरे-धीरे स्थायी दुकान बना लेता है। सड़क के बीच पत्थर रखकर मंदिर बना दिया जाता है और प्रशासन चुप रहता है क्योंकि वहाँ आस्था खड़ी हो जाती है। जब आस्था कानून पर भारी पड़ने लगती है, तब लोकतंत्र धीरे-धीरे भीड़तंत्र में बदलने लगता है।

अरावली पहाड़ियों का उदाहरण इस मानसिकता का राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका है। कागजों में पहाड़ को समतल भूमि घोषित कर कॉलोनियों और फ्लॉम हाउस में बदल दिया जाता है। यह केवल पर्यावरण का संकट नहीं है। यह भविष्य की पीढ़ियों से जमीन छीनने की प्रक्रिया है।

सत्ता का मनोविज्ञान और न्याय का संघर्ष



सुप्रीम कोर्ट कई बार सार्वजनिक संसाधनों के निजीकरण पर चेतावनी दे चुका है। लेकिन सत्ता का मनोविज्ञान अलग होता है। सत्ता खुद को स्थायी मानने लगती है और जनता को अस्थायी। 15 मई 2025 को पुणे में जंगल की 12 हेक्टेयर जमीन पर बहुमंजिला निर्माण की अनुमति अदालत ने रद्द कर दी। लेकिन सवाल वहीं रह गया—गलत अनुमति देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भारत में गलत फैसलों की कीमत अक्सर जनता चुकाती है, निर्णय लेने वाले नहीं।

छत्तीसगढ़: संसाधनों का स्वर्ग, संघर्ष का भूगोल

यदि भारत में भूमि संघर्ष का वास्तविक अध्ययन करना हो, तो छत्तीसगढ़ सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आता है। छत्तीसगढ़ को अक्सर 'धान का कटोरा' कहा जाता है। लेकिन यह राज्य केवल कृषि केंद्र नहीं है। यह भारत की खनिज अर्थव्यवस्था का हृदय भी है। यहाँ मौजूद है—

- विशाल कोयला भंडार
- लौह अयस्क के समृद्ध स्रोत
- बॉक्साइट और टिन जैसे खनिज
- घने वन क्षेत्र
- और सदियों से बसता आदिवासी समाज

विडंबना यह है कि संसाधनों से समृद्ध यह राज्य अधिकारों के संघर्ष से भी उतना ही भरा हुआ है।

वन अधिकार कानून: जमींदार और जमीनी सच्चाई

2006 का वन अधिकार कानून आदिवासी अधिकारों के इतिहास में महत्वपूर्ण कदम था। इस कानून ने पहली बार स्वीकार किया कि जंगल केवल सरकार का नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले समुदाय का भी है। छत्तीसगढ़ में इस कानून का क्रियान्वयन मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। कई क्षेत्रों में पट्टे वितरित हुए लेकिन अनेक दावे खारिज भी हुए। यह कानून कागज पर जितना मजबूत दिखता है, जमीन पर उतना ही जटिल साबित हुआ।

खनन परियोजनाएँ: विकास का वादा, विस्थापन की पीड़ा

बस्तर, कोरवा और सरगुजा छत्तीसगढ़ के खनन केंद्र हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर खनन परियोजनाएँ शुरू हुईं। सरकार का तर्क है—खनन से रोजगार और औद्योगिक विकास होगा। लेकिन विस्थापन का सामाजिक प्रभाव गहरा होता है। विस्थापन केवल घर बदलना नहीं होता। यह जीवन शैली के टूटने का नाम होता है। बस्तर के कई गांवों में आज भी लोग पृष्ठे हैं—'खनिज निकला, उद्योग लगा, लेकिन हमारे जीवन में क्या बदला?'

हसदेव अरण्य: लोकतंत्र की परीक्षा

छत्तीसगढ़ की भूमि राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है—हसदेव अरण्य। यह क्षेत्र एशिया के महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों में गिना जाता है। यह जैव विविधता और जल स्रोतों का केंद्र है। लेकिन यहाँ कोयला खनन को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है। स्थानीय समुदाय जंगल को अपनी जीवन रेखा मानता है। सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा का आधार



बताती है। हसदेव का संघर्ष केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। यह विकास मॉडल का मूल प्रश्न है—क्या विकास जनता की सहमति से होगा, या प्रशासनिक निर्णय से?

पैसा कानून और ग्रामसभा का अधिकार

आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन मजबूत करने के लिए पैसा कानून बनाया गया। यह कानून ग्रामसभा को जमीन और संसाधनों पर निर्णय का अधिकार देता है। लेकिन कई परियोजनाओं में ग्रामसभा की सहमति को लेकर विवाद उठते रहे हैं। सामाजिक संगठनों का आरोप है कि सहमति प्रक्रिया कई बार औपचारिक बन जाती है। सरकारी पक्ष कहता है कि विकास के लिए निर्णय आवश्यक हैं। सच शायद इन दोनों के बीच खड़ा है।

शहरी विस्तार और प्राकृतिक संतुलन



रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर तेजी से फैलते शहर हैं। लेकिन इस विस्तार ने जमीन का चरित्र बदल दिया है।

- जलाशय सिकुड़ रहे हैं
- चारागाह समाप्त हो रहे हैं
- सरकारी जमीनें निजी निर्माण में बदल रही हैं

रायपुर में हर मानसून में जलभराव इस असंतुलन की कहानी कहता है।

खनिज संपदा और स्थानीय विकास का सवाल

छत्तीसगढ़ देश की बिजली व्यवस्था का आधार है। लेकिन खनन क्षेत्रों के कई गांव अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जैसी योजनाएँ स्थानीय विकास के लिए बनाई गईं। लेकिन उनकी पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं।

न्याय की जटिल राह

भूमि विवादों के हजारों मामले अदालतों में लंबित हैं। आदिवासी और ग्रामीण समुदाय के लिए न्याय तक पहुँचना कठिन और महंगा है। दूसरी तरफ बड़े संस्थान मजबूत कानूनी संसाधनों से लैस होते हैं। यह असमानता लोकतंत्र के संतुलन को कमजोर करती है।

भविष्य का प्रश्न : जमीन या अस्तित्व

छत्तीसगढ़ की भूमि राजनीति केवल वर्तमान का प्रश्न नहीं है। यह आने वाली पीढ़ियों का सवाल है।

- जंगलों का कटाव
- स्वनन विस्तार



■ जल स्रोतों का क्षरण

ये सब भविष्य की सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं।

सत्ता बनाम जनता : लोकतंत्र की असली परीक्षा

दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन कभी जनता के प्रतीक थे। आज वे सुरक्षा घेरों में सत्ता के प्रतीक बन गए हैं। भारत की नौरक्षशी की 'स्टील फ्रेम' कहा जाता है। लेकिन जब वह फ्रेम जनता की आवाज सुनना बंद कर देता है, तब लोकतंत्र खोखला होने लगता है।

नैतिक राजनीति की वापसी का प्रश्न



विनोबा भावे का भूदान आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसमें नैतिक शक्ति थी। आज राजनीति में नैतिकता सबसे कमजोर मुद्दा बन चुकी है। यदि विनोबा भावे आज होते, तो शायद फिर वही सवाल पूछते—'जमीन किसकी है?' और शायद जवाब देते—'जमीन उस किसान की है जो उस पर पसीना बहाता है। जमीन उस नागरिक की है जो उस पर चलता है। जमीन उस बच्चे की है जो भविष्य में उस पर सपने देखेगा।'

नया नारा, नया लोकतंत्र

विनोबा भावे का नारा था—'सब भूमि गोपाल की।' लेकिन आज के भारत को शायद इसका नया अर्थ लिखना होगा—'सब भूमि जनता की और सरकार केवल उसकी संरक्षक।'।



परेड सिर्फ़ दिखावा नहीं, संदेश बन जाती है



आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान और ज़मीन पर चलते हथियार सिर्फ़ सैन्य प्रदर्शन नहीं थे। वे यह ऐलान थे कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में उपभोक्ता नहीं रहना चाहता, बल्कि निर्णायक शक्ति बनना चाहता है। कभी हथियारों के लिए दुनिया के दरवाज़े खटखटाने वाला भारत अब अपने रक्षा निर्यात के आँकड़े गर्व से गिनाता है।

77वाँ गणतंत्र दिवस इस अर्थ में अलग था कि वह केवल तिरंगे फहराने, परेड देखने या राष्ट्रगान सुनने तक सीमित नहीं रहा। वह भारत की बदली हुई मानसिकता, बदली हुई रणनीति और बदले हुए आत्मविश्वास का सार्वजनिक प्रदर्शन बन गया। यह दिन यह बताने आया कि भारत अब खुद को कैसे देखता है और दुनिया को कैसे दिखाना चाहता है। दिल्ली का कर्तव्य पथ अब राजधानी की एक सड़क भर नहीं है। वह एक मंच है, जहाँ सत्ता अपने इरादों, अपनी प्राथमिकताओं और अपने भविष्य के नक्शे को दृश्य भाषा में रखती है। इस बार का गणतंत्र दिवस 'विकसित भारत @2047' और 'वंदे मातरम् के 150 वर्ष' को समर्पित था। यह महज़ भावनात्मक संयोग नहीं था। यह अतीत के संघर्ष और भविष्य के संकल्प को एक ही प्रेम में रखने की सोची-समझी राजनीतिक अभिव्यक्ति थी। यह संदेश था कि राष्ट्र की स्मृति और राष्ट्र का लक्ष्य—दोनों पर एक ही सत्ता की वैचारिक मुहर है।

सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता का संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय समारंभ से कर्तव्य पथ तक का सफ़र एक औपचारिक परंपरा की तरह देखा जा सकता है, लेकिन राजनीति में कोई भी दृश्य केवल दृश्य

नहीं होता। यह उस भारत का संदेश था जो शहीदों को याद भी करता है और शत्रुओं को चेतावनी भी देता है। आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान और ज़मीन पर चलते हथियार सिर्फ़ सैन्य प्रदर्शन नहीं थे। वे यह ऐलान थे कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में उपभोक्ता नहीं रहना चाहता, बल्कि निर्णायक शक्ति बनना चाहता है। कभी हथियारों के लिए दुनिया के दरवाज़े खटखटाने वाला भारत अब अपने रक्षा निर्यात के आँकड़े गर्व से गिनाता है। यह आत्मविश्वास का संकेत है, लेकिन यह भी एक राजनीतिक भाषा है—जिसमें सुरक्षा, शक्ति और नेतृत्व को एक ही सूत्र में बाँध दिया गया है।

2047 का विजन: विकास, नियंत्रण और सत्ता का प्रतीक

2047 का लक्ष्य केवल विकास की समय-सीमा नहीं है। यह मौजूदा सत्ता की वह आकांक्षा है, जिसमें वह स्वयं को दीर्घकालिक वैचारिक सत्ता के रूप में स्थापित करना चाहती है। समर्थकों के लिए यह विजन है—एक स्पष्ट दिशा, एक मज़बूत नेतृत्व, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र। आलोचकों के लिए यही विजन वर्तमान के सवालियों को भविष्य के वादों से ढकने की रणनीति है। यही वह बिंदु है जहाँ गणतंत्र दिवस



का उत्सव राजनीति में बदल जाता है। 'मजबूत सरकार- सुरक्षित भारत' का नैरेटिव 2014 के बाद से लगातार निर्मित किया गया है और हर राष्ट्रीय मंच पर इसे और अधिक धार दी जा रही है। कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन केवल सुरक्षा का भरोसा नहीं देता, बल्कि यह संदेश भी गढ़ता है कि असहमति, बहस और सवाल के लिए जगह सीमित हो सकती है, लेकिन शक्ति के प्रदर्शन पर कोई समझौता नहीं होगा।

यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी यह संकेत देती है कि भारत अब केवल उभरती अर्थव्यवस्था नहीं रहा। वह उस वैश्विक टेबल पर बैठ चुका है जहाँ फैसले होते हैं—और कई बार दिशा भी वही तय करता है। यह कूटनीतिक सफलता है, लेकिन वैश्विक शक्ति बनने की परीक्षा केवल आर्थिक आँकड़ों या रक्षा समझौतों से नहीं होती। वह लोकतांत्रिक विश्वसनीयता से होती है। जिस देश की आंतरिक बहसें सिमटने लगे, जहाँ असहमति को संदेह की निगाह से देखा जाए, वहाँ वैश्विक मंच पर खड़े होने की नैतिक ज़मीन भी सवाल के घेरे में आती है।

सांस्कृतिक समावेशन या सत्ता का नियंत्रण ?

30 हजार जवान, 3000 कैमरे, 30 कंट्रोल रूम और AI आधारित निगरानी उपकरण—यह सब केवल आतंकी आशंकाओं का जवाब नहीं है। यह संकेत है कि राज्य अब प्रतिक्रिया नहीं, रोकथाम की नीति पर चल रहा है। लेकिन रोकथाम और निगरानी के बीच की रेखा बेहद महीन होती है। जब राज्य हर गतिविधि देख रहा हो, तब नागरिक की निजता, स्वतंत्रता और असहमति कहीं टिकेगी—यह सवाल गणतंत्र दिवस की परेड में नहीं दिखता, लेकिन लोकतंत्र की नींव में गूँजता है। सुरक्षा के नाम पर अगर समाज एक निगरानी राज्य में बदलने लगे, तो संविधान केवल एक दस्तावेज़ बनकर रह जाता है।

कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी सांस्कृतिक प्रस्तुति भर नहीं थी। वीर गुंडाधुर और 1910 के भूमकाल विद्रोह को राष्ट्रीय मंच पर लाना यह दर्शाता है कि आज का भारत केवल राजाओं और राजधानियों का इतिहास नहीं सुनाना चाहता। जंगलों और जनजातियों के संघर्षों को भी राष्ट्रीय चेतना

का हिस्सा बनाना चाहता है। यह स्वागत योग्य है, लेकिन जब इतिहास सत्ता के मंच पर आता है, तो वह निष्पक्ष नहीं रहता। डिजिटल जनजातीय संग्रहालय की झलक दरअसल एक राजनीतिक संकेत है कि अब इतिहास भी तकनीक, पहचान और सत्ता की नई भाषा में लिखा जाएगा। सवाल यह है कि यह समावेशन है या नियंत्रण—यह तय कौन करेगा ?

स्थानीय राजनीति और कल्याण योजनाएँ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विलासपुर में झंडा फहराना महज़ एक औपचारिक समारोह नहीं था। यह सत्ता का प्रतीक, राजनीतिक संदेश, और स्थानीय राजनीति के संकेतका मिश्रण था। जब कोई राज्य का मुखिया राजधानी के बाहर ऐसा कदम उठाता है, तो उसका अर्थ केवल प्रशासनिक नहीं होता। यह संदेश होता है—'सत्ता के केंद्र अब केवल दिल्ली या रायपुर तक सीमित नहीं हैं; विकास, नियंत्रण और राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र अब सीधे जनता के बीच पहुंचेगा।'



माच 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त करने का दावा राजनीतिक रूप से साहसिक भी है और जोखिम भरा भी। बंदूक और विकास को समानांतर चलाने की नीति कागज़ पर आकर्षक लगती है, लेकिन ज़मीन पर यह संतुलन बेहद नाजुक होता है। पुनर्वास, नियद नेज़ानार और तेज़ विकास योजनाएँ यह दर्शाती हैं कि राज्य सरकार अब केवल सैन्य समाधान की बात नहीं कर रही, लेकिन सवाल यह है कि क्या भरोसे के बिना विकास टिक सकता है?

धान खरीदी के आँकड़े, महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना—ये केवल कल्याणकारी घोषणाएँ नहीं हैं। ये राजनीतिक रणनीतियाँ हैं, जिनका लक्ष्य ग्रामीण और महिला वोट बैंक को स्थिर रखना है। मुख्यमंत्री का भाषण यह भी संकेत देता है कि अब राज्य सरकारस्थानीय स्तर पर सत्ता का स्थायी प्रभावस्थापित करना चाहती है। लोकतंत्र में यह अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन जब कल्याण योजनाएँ दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन के बजाय चुनावी स्थिरता का औज़ार बन जाएँ, तो नीति और राजनीति के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है।

वंदे मातरम् बनाम राष्ट्रगान

इसी गणतंत्र दिवस के आसपास वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने की मांग फिर उठी। सवाल यह नहीं है कि वंदे मातरम् का सम्मान कम है या अधिक। सवाल यह है कि जब संविधान सभा ने स्पष्ट रूप से जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया, तो यह बहस बार-बार क्यों उठती है? 2012 में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट कर चुकी है कि राष्ट्रगीत पर राष्ट्रगान जैसा प्रोटोकॉल लागू नहीं होता। यह भी तथ्य है कि वंदे मातरम् से जुड़े निर्णय किसी एक नेता के नहीं, बल्कि सामूहिक समिति के थे, जिनमें सुभाष चंद्र बोस जैसे नाम शामिल थे। फिर इसे बार-बार धार्मिक चरम से देखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर वंदे मातरम् को राष्ट्रगान बना भी दिया जाए, तो क्या इससे राष्ट्रभक्ति बढ़ जाएगी? या असली सवाल यह है कि क्या देश की मिट्टी को सलाम करना धर्म से बड़ा नहीं होना चाहिए?

वास्तविक भारत: परेड के बाहर

कर्तव्य पथ की चमक के बाहर एक दूसरा भारत खड़ा है, जो कुछ और सवाल पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ के गौरैला-पेंड्रा से खबर आती है कि प्रेम करने की सज़ा में एक विधवा को अर्धनग्न कर गाँव में घुमाया गया। प्रयागराज में एक शंकराचार्य अपनी पहचान साबित कर रहे हैं—कोई वोटर होने का प्रमाण दे रहा है, कोई नागरिकता का। GC समानता की बात करता है, लेकिन ज़मीन पर असमानता और कठोर होती जा रही है। यह भारत परेड में नहीं दिखता, लेकिन यही भारत लोकतंत्र की असली परीक्षा है।

77वां गणतंत्र दिवस यह साफ़ करता है कि भारत अब केवल लोकतंत्र होने पर गर्व नहीं करता और न ही सिर्फ सैन्य शक्ति दिखा रहा है। वह लोकतंत्र, तकनीक, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक पहचान—इन सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। कर्तव्य पथ से लेकर बिलासपुर तक संदेश एक ही है कि भारत आत्मविश्वास से भरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि उस भविष्य में संविधान, करुणा और विवेक कितने सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि गणतंत्र केवल शक्ति से नहीं चलता—वह संवेदनशीलता से जीवित रहता है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनायें





संस्कृति, सुरक्षा और विकास के त्रिकोण में छत्तीसगढ़



बस्तर के संदर्भ में पढ़ा जाए तो यह केवल सांस्कृतिक प्रशंसा नहीं, बल्कि लंबे समय से उपेक्षित समाज को विश्वास में लेने की कोशिश भी है। केंद्र सरकार का यह रुख बताता है कि बस्तर को अब सिर्फ 'सुरक्षा समस्या' के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि उसे सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ इस समय केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति और नीति-निर्माण के केंद्र में खड़ा दिखाई देता है। बस्तर पंडूम में राष्ट्रपति का आगमन, रायपुर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा—इन तीनों घटनाओं ने राज्य को एक साथ संस्कृति, सुरक्षा और विकासके विमर्श में ला खड़ा किया है। यह संयोग नहीं, बल्कि संकेत है।

बस्तर पंडूम: राष्ट्रपति का संदेश और आदिवासी अस्मिता

बस्तर, जिसे दशकों तक नक्सल हिंसा और पिछड़ेपन की प्रतीकात्मक छवि में देखा गया, वहां राष्ट्रपति का पहुंचना अपने आप में एक राजनीतिक और सामाजिक वक्तव्य है। बस्तर पंडूम जैसे आयोजन में राष्ट्रपति की उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि आदिवासी समाज की संस्कृति अब केवल लोक उत्सव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है।

राष्ट्रपति ने मंच से स्पष्ट शब्दों में कहा—
'आदिवासी समाज की संस्कृति भारत की मूल आत्मा है। बस्तर की परंपराएँ केवल स्थानीय पहचान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विरासत हैं।'



उन्होंने यह भी जोड़ा—

‘विकास तभी सार्थक होगा जब उसमें स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान शामिल होगा।’

इन शब्दों को बस्तर के संदर्भ में पढ़ा जाए तो यह केवल सांस्कृतिक प्रशंसा नहीं, बल्कि लंबे समय से उपेक्षित समाज को विश्वास में लेने की कोशिश भी है। केंद्र सरकार का यह रुख बताता है कि बस्तर को अब सिर्फ ‘सुरक्षा समस्या’ के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि उसे सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अमित शाह का तीन दिवसीय दौरा: नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक संकेत

राष्ट्रपति के सांस्कृतिक संदेश के समानांतर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा सुरक्षा और रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब केंद्र सरकार नक्सलवाद के खिलाफ ‘फाइन्डल पुश’ की बात कर रही है।

अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान साफ कहा— ‘नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन अब इसका अंत तय है।’

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि— ‘केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बस्तर सहित पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति और विकास का नया अध्याय लिखेंगे।’

शाह का जोर केवल सुरक्षा अभियानों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि नक्सलवाद से लड़ाई केवल बंदूक से नहीं, बल्कि विकास से जीती जाएगी।

उनके शब्दों में— ‘सुरक्षा के साथ-साथ शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास का माहौल बनाया जा रहा है।’

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह दौरा केंद्र की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सुरक्षा और विकास को एक

साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि नक्सलवाद की सामाजिक जमीन को कमजोर किया जा सके।

रायपुर में मनोहर लाल खट्टर विकास मॉडल की व्याख्या

इसी क्रम में रायपुर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने छत्तीसगढ़ के शहरी और आधारभूत विकास को राष्ट्रीय एजेंडे से जोड़ने की कोशिश की। खट्टर ने साफ किया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को तेजी से विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा— ‘छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और केंद्र सरकार राज्य को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास योजनाओं के माध्यम से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।’

शहरीकरण की चुनौतियों पर बात करते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा— ‘विकास का उद्देश्य केवल शहरों का विस्तार नहीं, बल्कि नागरिकों को जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।’

खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह संदेश स्पष्ट था कि रायपुर जैसे शहरों को भविष्य के शहरी मॉडल के रूप में विकसित किया जाना है, जहां बुनियादी सुविधाएं, आवास और परिवहन व्यवस्था प्राथमिकता होंगी।

तीन घटनाएं, एक साझा संदेश

अगर इन तीनों घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर साफ होती है।

बस्तर में राष्ट्रपति का आगमन सांस्कृतिक सम्मान का संदेश देता है, अमित शाह का दौरा सुरक्षा और स्थिरता का भरोसा, और मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

यह त्रिवेणी बताती है कि छत्तीसगढ़ अब केवल संसाधनों का राज्य नहीं, बल्कि नीति, प्रयोग और राजनीतिक प्राथमिकताओं का केंद्र बन रहा है।

आगे की राह और असली परीक्षा

हालांकि, चुनौतियां अभी भी कम नहीं हैं। बस्तर जैसे क्षेत्रों में विकास योजनाओं को जमीन पर उतारना और स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना सबसे बड़ी परीक्षा है। शहरी विकास के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा।

अब सवाल यह नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि यह है कि कहे गए शब्द जमीन पर कितना उतरते हैं।

अगर संस्कृति के सम्मान, सुरक्षा की दृढ़ता और विकास की योजनाएं वास्तव में एक-दूसरे से जुड़ पाईं, तो छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में केवल खबरों का विषय नहीं, बल्कि देश के लिए एक मॉडल बन सकता है।



स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण सशक्तिकरण छत्तीसगढ़ के विकास का संयुक्त सूत्र



एक ओर स्वास्थ्य विभाग शरीर की सुरक्षा और रोग नियंत्रण की बात करता है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास विभाग जीवन की आधारभूत संरचना—आवास, सड़क, रोजगार और प्रशासनिक पहुंच—को मजबूत करने का दावा करता है। परंतु असली प्रश्न यह है कि क्या ये दोनों विकास धाराएं मिलकर समाज की समग्र गुणवत्ता सुधार रही हैं, या अभी भी अलग-अलग रास्तों पर चल रही हैं।

लोकतंत्र में सरकारें जब अपने कार्यकाल का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती हैं, तो मंच पर उपलब्धियों की चमक दिखाई देती है। आंकड़ों की श्रृंखला, योजनाओं की लंबी सूची, बजट के बढ़ते ग्राफ और उद्घाटन की तस्वीरें—ये सब विकास के प्रतीक बनकर प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र का सबसे सशक्त सत्य यह है कि विकास का अंतिम प्रमाण सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन अनुभवों में दर्ज होता है। जब एक किसान अपने खेत तक पक्की सड़क के कारण समय पर पहुंच पाता है, जब एक आदिवासी परिवार बीमारी के भय से मुक्त होकर इलाज तक पहुंच पाता है, और जब एक महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करती है—तभी विकास को अवधारणा जीवंत होती है।

छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में स्वास्थ्य



मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी व्यापक लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा बनकर सामने आई है। पहली नजर में यह दो विभागों की उपलब्धियों का प्रशासनिक विवरण प्रतीत होता है, लेकिन यदि इसे गहराई से देखा जाए तो यह राज्य के विकास मॉडल की वैचारिक दिशा को भी रेखांकित करता है। एक ओर स्वास्थ्य विभाग शरीर की सुरक्षा और रोग नियंत्रण की बात करता है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास विभाग जीवन की आधारभूत

संरचना—आवास, सड़क, रोजगार और प्रशासनिक पहुंच—को मजबूत करने का दावा करता है। परंतु असली प्रश्न यह है कि क्या ये दोनों विकास धाराएं मिलकर समाज की समग्र गुणवत्ता सुधार रही हैं, या अभी भी अलग-अलग रास्तों पर चल रही हैं।

स्वास्थ्य केवल अस्पताल नहीं, जीवन परिस्थितियों का परिणाम

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में रोकथाम आधारित स्वास्थ्य मॉडल को प्राथमिकता दी गई है। मलेरिया दर में कमी, टीबी मुक्त पंचायत अभियान और सिकल सेल स्क्रीनिंग जैसे प्रयास यह संकेत देते हैं कि सरकार बीमारी के उपचार से पहले उसकी रोकथाम की दिशा में सोच रही है। यह दृष्टिकोण आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है।

लेकिन स्वास्थ्य केवल चिकित्सा संस्थानों की संख्या बढ़ाने से नहीं बनता। स्वास्थ्य जीवन परिस्थितियों का समग्र परिणाम होता है। यदि किसी गांव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है, यदि रोजगार अस्थिर है, यदि परिवार सुरक्षित आवास से वंचित है, तो स्वास्थ्य योजनाएं केवल सीमित प्रभाव ही छोड़ पाती हैं। यही वह बिंदु है जहां ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य नीति एक-दूसरे से जुड़ जाती हैं।

दरअसल स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास सामाजिक संरचना के दो पहिये हैं। यदि इनमें संतुलन नहीं होगा, तो विकास अधूरा ही रहेगा। उदाहरण के लिए सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान को ही देखें। बीमारी की पहचान निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन मरीज को निरंतर दवा, पोषण और मानसिक सहयोग तभी मिल सकता है जब उसका परिवार आर्थिक रूप से स्थिर हो। यह स्थिरता केवल चिकित्सा व्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास योजनाओं से संभव होती है।

आज राज्य के कई क्षेत्रों में मरीजों की पहचान हो रही है, लेकिन उपचार की निरंतरता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह केवल स्वास्थ्य विभाग की कमजोरी नहीं, बल्कि सामाजिक ढांचे की भी समस्या है। जब

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से परिवार को सुरक्षित घर मिलेगा, जब महिला स्व-सहायता समूह आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करेंगे, तभी स्वास्थ्य कार्यक्रम स्थायी परिणाम दे पाएंगे।

नियुक्तियां बनाम जमीनी वास्तविकता

सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हजारों पदों पर नियुक्ति का दावा किया है। यह प्रशासनिक दृष्टि से निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों की जमीनी हकीकत अभी भी अलग तस्वीर प्रस्तुत करती है। इन क्षेत्रों के कई ब्लॉकों में आज भी मरीज अनौपचारिक चिकित्सा व्यवस्था—जिसे आम बोलचाल में 'कंपाउंडर संस्कृति' कहा जाता है—पर निर्भर हैं।

यह समस्या केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की नहीं है। यह ग्रामीण प्रशासनिक ढांचे का भी प्रश्न है। चिन क्षेत्रों में सड़क अथूरी हैं, जहां आवास सुविधाएं सीमित हैं और सामाजिक ढांचा कमजोर है, वहां डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का लंबे समय तक टिकना कठिन हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण अधोसंरचना को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। दोनों व्यवस्थाएं एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

अधोसंरचना विकास बनाम सेवा गुणवत्ता

छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, जिला अस्पतालों का सुदृढीकरण और सेन्ट्री मानसिक स्वास्थ्य संस्थान जैसी परियोजनाएं विकास की सकारात्मक दिशा का संकेत देती हैं। लेकिन भारत की प्रशासनिक परंपरा में अक्सर यह देखा गया है कि भवन पहले बनते हैं और सेवाएं बाद में विकसित होती हैं।

मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का निर्माण निश्चित रूप से एक प्रगतिशील कदम है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का समाधान केवल अस्पतालों से नहीं आता। इसके लिए समुदाय आधारित मॉडलिंग, सामाजिक जागरूकता और पंचायत स्तर पर संवाद आवश्यक होता है। यदि मानसिक स्वास्थ्य को सामाजिक विमर्श का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो संस्थान केवल उपचार केंद्र बनकर रह जाएंगे।

आयुज्ज्वान योजना और नीति का द्वंद्व

आयुज्ज्वान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए जीवन रक्षक सिद्ध हुई है। इस योजना ने लाखों परिवारों को महंगे इलाज से आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। लेकिन बीमा आधारित स्वास्थ्य मॉडल अपने साथ एक दीर्घकालिक नीति चुनौती भी लेकर आता है।

जब सरकारी अस्पतालों की गुणवत्ता कमजोर होती है, तो मरीज निजी अस्पतालों की ओर जाते हैं। इससे सरकारी संसाधन निजी स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होने लगते हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल दक्षता बढ़ा सकता है, लेकिन यदि इसमें सामाजिक न्याय का संतुलन नहीं रहा तो ग्रामीण गरीब स्वास्थ्य सेवाओं से दूर हो सकता है। बस्तर अस्पताल विवाद इसी नीति द्वंद्व का प्रतीक माना जा सकता है।

बस्तर जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा केवल सुविधा नहीं होती, बल्कि यह राज्य और आदिवासी समाज के बीच विश्वास का माध्यम भी होती है। यदि स्वास्थ्य सेवाओं को स्थानीय संवेदनशीलता और सांस्कृतिक समझ के साथ विकसित नहीं किया गया, तो यह विश्वास कमजोर हो सकता है।

डिजिटल प्रशासन और सामाजिक असमानता

अटल डिजिटल केंद्र और ग्राम एप जैसे प्रयास प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। डिजिटल व्यवस्था पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने की क्षमता रखती है। लेकिन डिजिटल क्रांति ग्रामीण भारत के सामने नया सामाजिक प्रश्न भी खड़ा कर रही है।

क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से सक्षम है? बुजुर्ग नागरिक, आदिवासी समुदाय और कम शिक्षित वर्ग अक्सर डिजिटल प्रक्रियाओं से

दूरी महसूस करते हैं। यदि डिजिटल व्यवस्था प्रशिक्षण और जनजागरूकता से नहीं जुड़ी, तो यह सुविधा के बजाय असमानता का कारण बन सकती है।

अधोसंरचना और नवसलवाद का जटिल संबंध

सरकार का मानना है कि अधोसंरचना विकास नवसलवाद के समाधान का प्रमुख माध्यम है। सड़क, बिजली और संचार नेटवर्क प्रशासनिक पहुंच को मजबूत करते हैं और विकास को गति देते हैं। यह दृष्टिकोण आंशिक रूप से सही भी है।

लेकिन नवसलवाद केवल सुरक्षा या विकास का प्रश्न नहीं है। यह संसाधन, पहचान और अधिकार से जुड़ा सामाजिक संघर्ष भी है। यदि विकास परियोजनाओं के साथ स्थानीय समुदाय की भागीदारी, शिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं जुड़े, तो अधोसंरचना स्थायी समाधान नहीं बन पाएगी।

लोकतंत्र का संतुलन और मतदाता की बदलती सोच

छत्तीसगढ़ की राजनीति वर्तमान में दो विकास दृष्टिकोणों के बीच खड़ी दिखाई देती है। सरकार विकास की गति और उपलब्धियों को प्रस्तुत कर रही है, जबकि विपक्ष विकास की गुणवत्ता और प्रभाव का प्रश्न उठा रहा है। लोकतंत्र में यह टकराव आवश्यक है क्योंकि गति बिना गुणवत्ता के अस्थायी होती है और गुणवत्ता बिना गति के प्रभावहीन।

आज ग्रामीण मतदाता केवल घोषणाओं के आधार पर निर्णय नहीं ले रहा है। वह योजना के वास्तविक लाभ, प्रशासनिक व्यवहार और आर्थिक स्थिरता जैसे आधारों पर सरकार का मूल्यांकन कर रहा है। यह परिवर्तन लोकतंत्र को परिष्कृतता का संकेत है।

समग्र सामाजिक नीति की अनिवार्यता

भविष्य की सबसे बड़ी नीति चुनौती यही है कि स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को अलग-अलग विभागों के रूप में नहीं बल्कि संयुक्त सामाजिक नीति के रूप में विकसित किया जाए। जब मरीज अस्पताल जाने से पहले आर्थिक भय से मुक्त होगा, जब डॉक्टर गांव को सेवा केंद्र के रूप में स्वीकार करेंगे, जब आवास केवल दीवारों का ढांचा नहीं बल्कि जीवन की स्थिरता बनेगा, और जब डिजिटल व्यवस्था सुविधा बनेगी—बाधा नहीं—तभी विकास का वास्तविक अर्थ सामने आएगा।

संक्रमण काल में खड़ा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ आज एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। यह वह समय है जब राज्य को तय करना है कि विकास आंकड़ों का उत्सव बनेगा या जनता के जीवन का वास्तविक परिवर्तन। सरकार की नीतियां, प्रशासनिक ढांचा और सामाजिक भागीदारी मिलकर ही इस प्रश्न का उत्तर तय करेंगे।

लोकतंत्र को सबसे बड़ी शक्ति यही है कि अंतिम रिपोर्ट कार्ड सरकार नहीं, जनता लिखती है। आंकड़े विकास का दावा कर सकते हैं, लेकिन जनता का अनुभव ही उस दावे की सच्चाई तय करता है। यदि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित कर पाया, तो यह राज्य केवल विकास मॉडल नहीं बल्कि समग्र सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण बन सकता है।



सुशासन से समृद्धि की ओर छत्तीसगढ़



एमन लोन्हरे, उप संचालक (जनसंपर्क)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 वर्ष के मुख्यमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ राज्य में विकास का एक नया आयाम गढ़कर राज्य के नागरिकों के दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। विष्णुदेव साय जनता के बीच के एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिसकी सदाशयता और दूरगामी योजनाओं से प्रदेश में विकास और प्रगति का राह आसान हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं। इस दृष्टि से आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाले वे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश में हाल ही में पुलिस महानिदेशकों एवं पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह शामिल हुए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने एक साल के भीतर छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के खाते में 52 हजार करोड़ रुपए अंतरित कर उन्हें उत्साह से भर दिया है। धान खरीदी समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया गया है। 52 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में आने से वे खेती किसानों में भरपूर निवेश कर रहे हैं और इससे बाजार भी गुलजार हुए हैं जिससे शहरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिख रहा है। ट्रैक्टर आदि की बिक्री ने रिकार्ड अंकड़ा छू लिया है। धान का उचित मूल्य मिलने से किसानों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई और गत वर्ष 25 लाख 72 हजार किसानों ने 149 लाख 25 हजार मीट्रिक टन रिकार्ड धान बेचा। सरकार बनने के दूसरे दिन ही केबिनेट की बैठक कर मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता के बीच और हर समुदाय के बीच एक ऐसा पुल बनाना जानते हैं जिससे सभी एक दूसरे से जुड़ सकें और सभी प्रदेश के हित में अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर सकें।

विष्णु देव साय ने अपने दो साल के संक्षिप्त कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को सम्पूर्ण देश में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। बहुत कम समय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता के बीच जाकर पूरे प्रदेश की जनता का विश्वास जीता है और न

केवल विश्वास जीता है बल्कि उनके हित को ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है जिससे छत्तीसगढ़ का समग्र विकास सम्भव हो पाया है। यह केवल और केवल विष्णुदेव साय जैसे एक संवेदनशील, कर्मठ तथा ऊर्जावान मुख्यमंत्री ही सम्भव कर सकते हैं। नक्सल हिंसा प्रभावित गांवों में निचद नेछारान योजना के माध्यम से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी मूलभूत सुविधाएं दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। प्रदेश में अब तक 69 सुरक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते ही प्रदेश की समस्त महिलाओं को महतारी वंदन योजना जैसी एक लाभकारी योजना का सीमांत दिया है। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की महिलाओं को हर माह एक हजार रुपए की राशि दी जाती है जिससे वे स्वावलंबी बन सकें एवं स्वयं का रोजगार भी प्राप्त कर सकें। साथ ही प्रदेश भर के किसानों को 2 साल का बाकया बोनस और 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जैसे वादां को पूरा कर छत्तीसगढ़ की किसानों का मान बढ़ाया है। प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति से राज्य में अब तक 7.69 लाख रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।

खरीफ सीजन में उपज का वाजिब कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान का उपार्जन किया गया। सरकार किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की है। मुख्यमंत्री श्री साय की नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से किसानों के खाते में 52 हजार करोड़ रुपए की राशि अंतरित (ट्रांसफर) हुई है। प्रदेश के नगर पालिका चुनाव में ऐतिहासिक जनसहारा प्राप्त हुआ। प्रदेश में अब ट्रिपल इंजन की सरकार से नगरों का सर्वांगीण विकास होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों के अदम्य साहस और सरकार के निरंतर प्रयासों से नक्सलवाद अब अंतिम सांस ले रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमितशाह का संकल्प है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। वो संकल्प पूरा होते साफ दिख रहा है विशेषकर बस्तर क्षेत्र में, जो वर्षों से विकास की मुख्यधारा से अछूता रहा है। वहां अब विकास की गंगा बहेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में बीते 02 वर्षों में 529 नक्सली मारे जा चुके हैं, 1975 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 2628 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। प्रदेश के बस्तर अंचल में आतंक का पर्याय रहे हार्डकोर नक्सली लीडर बमबराजू, लक्ष्मी नरसिम्हा चालम उर्फ सुभाकर, और माडवो हिड्डमा को न्यूट्रालाइज किया गया इन पर करोड़ों का इनाम घोषित था।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग की बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पीएम आवास योजना, कृषक उन्नति योजना, निचद नेछा नर, अछरा निर्माण योजना जैसी योजनाओं का शुभारम्भ किया है और जनता के बीच अपनी एक अलग छवि निर्मित की है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता के बीच और हर समुदाय के बीच एक ऐसा पुल बनाना जानते हैं जिससे सभी एक दूसरे से जुड़ सकें और सभी प्रदेश के हित में अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी कर सकें। उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय प्रदेश की जनता को समर्पित कर यह सिद्ध कर दिया है कि उनका जीवन केवल उनका नहीं है अपितु प्रदेश की जनता की निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित है।

वे सही मायने में एक ऐसे जननेता हैं जिनके लिए जनता ही सब कुछ हैं। ऐसे सेवाभावी और लोकप्रिय जनसेवक बहुत कम होते हैं जिनके लिए जनता का विकास और जनता का साथ ही सबसे महत्वपूर्ण हितका है। यह सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरवान्वित होने का विषय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके अपने बीच के लोकप्रिय नेता हैं जिनके लिए प्रदेश की जनता की खुशहाली ही सर्वोपरि है।



जहाँ शब्दों ने शहर से दिल तक का सफ़र तय किया

रायपुर साहित्य उत्सव-2026

कुछ आयोजन होते हैं जो कैलेंडर की तारीखों में सिमट जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो समाज की स्मृति में दर्ज हो जाते हैं। रायपुर साहित्य उत्सवदूपरे प्रकार का आयोजन है। तीन दिनों तक रायपुर केवल छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक राजधानी नहीं था—वहविचारों की राजधानी बन गया था। ऐसी राजधानी, जहाँ सत्ता का शोर नहीं था, बल्कि संवाद की गूंज थी। जहाँ मंच से नारे नहीं, प्रश्न उतर रहे थे—और श्रोता सिर्फ सुन नहीं रहे थे, सोच रहे थे।



नरेन्द्र पाण्डेय

रायपुर साहित्य उत्सव सिर्फ किताबों, कविताओं और विमर्शों का सालाना आयोजन नहीं रहा। यह उस भारत की बौद्धिक नब्बू बनता जा रहा है, जो महानगरों के बाहर भी सोचता है, सवाल

करता है और दिशा तय करता है। तीन दिनों तक नवा रायपुर का पुरखौती मुकांगन केवल एक आयोजन स्थल नहीं था—वह एक चलता-फिरता वैचारिक मंच था, जहाँ शब्द मंच से उतरकर समाज से संवाद कर रहे थे। यह उत्सव इसलिए महत्वपूर्ण नहीं था कि यहाँ कितने बड़े नाम आए, बल्कि इसलिए कि यहाँ

किस तरह की बातचीत हुई। साहित्य, संस्कृति, तकनीक, राष्ट्र, नैतिकता, लोकबोध और भविष्य—ये सब विषय किसी औपचारिक सेमिनार की तरह नहीं, बल्कि समाज के भीतर चल रही बेचैनी की तरह सामने आए।

साहित्य का प्रश्न : मनोरंजन या जिम्मेदारी?

उत्सव की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसने साहित्य को 'मनोरंजन' या 'एलीट बौद्धिक विलास' के दायरे से बाहर निकालकर सामाजिक उत्तरदायित्व के केंद्र में खड़ा किया। लगभग हर सत्र में यह प्रश्न अंतर्धारा की तरह बहता रहा—आज के समय में साहित्य की भूमिका क्या है? यह प्रश्न इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि डिजिटल युग में साहित्य को अक्सर 'धीमा माध्यम' मान लिया गया है। लेकिन रायपुर साहित्य उत्सव ने इस धारणा को उलट दिया। यहाँ साहित्य तेज़ खबरों के शोर के बीच टहकर सोचने की कला सिखाता दिखा।

संघ, समाज और सौ वर्षों की यात्रा



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सौ वर्षों की यात्रा पर केंद्रित सत्र ने यह स्पष्ट किया कि संघ को केवल राजनीतिक चरम से देखना एक सरलीकरण है। विचारक एवं लेखक राम माधव ने स्पष्ट शब्दों में कहा—'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई गुप्त या सदस्यता-आधारित संगठन नहीं है। इसकी शाखाएँ खुले मैदानों में लगती हैं—जहाँ कोई भी आकर देख सकता है, समझ सकता है और सवाल कर सकता है।'

राम माधव का वक्तव्य प्रचारात्मक नहीं, बल्कि वैचारिक था। उन्होंने भारतीय बौद्धिक परंपरा को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए कहा—'किसी भी जीवित राष्ट्र के लिए उसका बौद्धिक विमर्श उसकी प्राणवायु होता

है।' यह वक्तव्य केवल संघ के संदर्भ में नहीं, बल्कि समूचे भारतीय समाज के लिए था। उन्होंने वेद, उपनिषद और दर्शन को परंपरा का उल्लेख करते हुए यह रेखांकित किया कि भारतीय चिंतन मौलिक है, तर्कसंगत है और मानवीय मूल्यों की कसौटी पर खरा उतरता है।

GDP से आगे समाज

विकास की अवधारणा को केवल GDP तक सीमित रखने पर सवाल उठे। चर्चा व्यक्तिवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, परिपत्र अर्थव्यवस्था और सामाजिक पूंजी तक पहुँची। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि केवल आर्थिक वृद्धि राष्ट्र को सशक्त नहीं बनाती, बल्कि नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता के साथ किया गया विकास ही टिकाऊ होता है। यह बहस विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत 2047 के 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। सवाल यह नहीं कि हम कितने अमीर होंगे—सवाल यह है कि हम कैसे मनुष्य बनेंगे।

धर्म, सिनेमा और सामूहिक चेतना

धार्मिक फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों पर केंद्रित सत्र ने मनोरंजन उद्योग को केवल TRP के तराजू पर नहीं तौला। यहाँ धर्म, नैतिकता और समकालीन समाज के रिश्ते पर गंभीर विमर्श हुआ।

रिंतीश भारद्वाज ने छत्तीसगढ़ और झारखंड की आदिवासी परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र कथाओं का जीवित संग्रहालय है। उन्होंने कहा— 'राम और कृष्ण को केवल बाहर नहीं, अपने भीतर भी खोजने की आवश्यकता है।' उन्होंने माता-पिता की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि संस्कारों की शुरुआत घर से होती है। यह वक्तव्य धार्मिक कम और मानवीय अधिक था।

तकनीक, AI और मनुष्य का भविष्य

ट्रिपल IT, नवा रायपुर के निदेशक डॉ. ओमप्रकाश व्यास ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करते हुए बताया कि AI कोई अचानक पैदा हुई तकनीक नहीं है। यह दशकों के शोध का परिणाम है।

"ChatGPT के आने के बाद पिछले तीन वर्षों में AI का विस्तार अभूतपूर्व रहा है।' लेकिन तकनीक को लेकर चिंता भी सामने आई। वरिष्ठ वक्ताओं ने यह सवाल उठाया कि मानव और मशीन का रिश्ता किस दिशा में जाएगा। भारतीय ऋषि सूचना नहीं, ज्ञान की बात करते थे—यह फर्क आज के डिजिटल दौर में और अधिक प्रासंगिक हो गया है।



रायपुर साहित्य उत्सव को यदि केवल कविताओं, पुस्तकों और लेखकों की उपस्थिति तक सीमित किया जाए, तो यह उसके साथ अन्याय होगा। यह उत्सवसमाज, संस्कृति, राष्ट्र और तकनीकके बीच चल रहे संघर्ष और समन्वय का मंच था। यहाँ साहित्य सत्ता से सवाल करता दिखा— और सत्ता, पहली बार, साहित्य की भाषा में जवाब देती दिखा। यही इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।

भाषा, वेद और आधुनिक विज्ञान

डॉ. गोपाल कमल ने भाषा के उद्भव और मनुष्य की चेतना तक उसकी यात्रा को साइकोलिंग्विस्टिक दृष्टि से समझाया। उन्होंने महेश्वर सूत्रों और आधुनिक AI नेटवर्क के बीच वैचारिक समानताओं की ओर संकेत किया— यह दिखाता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा आधुनिक विज्ञान से टकराती नहीं, संवाद करती है।

पत्रकारिता, राष्ट्रवाद और सत्य



वरिष्ठ पत्रकार रुबिका लियाकत और छत्तीसगढ़ साहित्य मंडल के अध्यक्ष शशांक शर्मा के बीच संवाद उत्सव का सबसे चर्चित सत्र रहा। रुबिका लियाकत ने कहा— 'मेरी प्रतिबद्धता किसी व्यक्ति या विचारधारा से नहीं, बल्कि सत्य, नैतिकता और भारत से है।' उन्होंने युवाओं को सोशल मीडिया के त्वरित और अपूर्ण कंटेंट से सावधान रहने की सलाह दी और तथ्यों की स्वयं जांच पर जोर दिया। गणेश शंकर विद्यार्थी के साहस का उल्लेख करते हुए उन्होंने

पत्रकारिता को सेवा और जोखिम दोनों बताया।

लोकगीत : छत्तीसगढ़ की आत्मा

लोक साहित्य पर केंद्रित सत्र ने यह साबित किया कि छत्तीसगढ़ केवल खनिजों की भूमि नहीं, बल्कि संवेदनाओं की धरती है। डॉ. बी. लाल यादव ने कहा कि लोकगीत किसी एक रचनाकार के नहीं, पूरे समाज के होते हैं। शकुंतला तारा और डॉ. विनय कुमार पाठक ने लोकगीतों की भाषिक और भावनात्मक समृद्धि पर प्रकाश डाला। यह सत्र साहित्यिक कम और सांस्कृतिक अधिक था।

युवा स्वर : भविष्य की आहट

उत्सव का सबसे आशावादी पहलू युवाओं की भागीदारी रही। कहानी, कविता और संवाद सत्रों में युवाओं ने यह भरोसा दिया कि साहित्य का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। एक युवा कवि का कहना— 'पहली बार लगा कि मेरी कविता मेरी डायरी से बाहर निकलकर किसी और तक पहुँची है।' यह वक्तव्य किसी पुरस्कार से बड़ा था।

समापन सत्र में राज्यपाल रोमन डेका ने कहा— 'इंटरनेट से भरी इस दुनिया में भी प्रिंट और साहित्य का महत्व हमेशा बना रहेगा।' यह कथन औपचारिक नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक घोषणा थी।

रायपुर साहित्य उत्सव ने यह साबित किया कि साहित्य किसी महानगर की बंपोती नहीं। विचारों को किसी आलीशान मंच की जरूरत नहीं होती—बस एक ईमानदार संवाद चाहिए। तीन दिनों तक रायपुर प्रशासनिक राजधानी नहीं रहा—वह वैचारिक राजधानी बन गया। और शायद यही साहित्य की सबसे बड़ी जीत है।



हमारा लक्ष्य बिजली देना नहीं, जीवन में उजाला लाना है



भूपेंद्र सवन्नी
अध्यक्ष, क्रेडा

क्रेडा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा केवल तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम

बनती दिखाई दे रही है। सौर सुजला योजना से किसानों की सिंचाई सुविधा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता, नक्सल प्रभावित इलाकों में रोशनी और पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक प्रयासों ने राज्य के विकास को नई दिशा दी है। इन उपलब्धियों और भविष्य की ऊर्जा सोच को समझने के लिए लाइफ वर्सिटी के संपादक नरेन्द्र पाण्डेय ने क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी से विशेष बातचीत की।

छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के एक छोटे से गांव में जब पहली बार सोलर हाई मास्ट की रोशनी जली, तो वह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी। वह वर्षों के अंधकार, अलगाव और विकास की प्रतीक्षा पर विजय की कहानी थी। उस रोशनी के नीचे खेलते बच्चों की मुस्कान और पहली बार सुरक्षित महसूस करते ग्रामीणों की आंखों में चमक — यही वह दृश्य है, जिसे क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी छत्तीसगढ़ के विकास की असली तस्वीर मानते हैं।

भूपेंद्र सवन्नी ऊर्जा को कभी केवल मेगावाट और किलोवाट में नहीं मापते। वे इसे जीवन की गुणवत्ता से जोड़कर देखते हैं।

उनसे बातचीत के दौरान यह स्पष्ट होता है कि उनके लिए सौर ऊर्जा एक योजना नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का मिशन है।

‘ऊर्जा तभी सार्थक है जब वह जीवन बदल दे’

भूपेंद्र सवन्नी कहते हैं —

‘हमारा प्रयास कभी केवल बिजली देना नहीं रहा। हमारा उद्देश्य यह रहा कि सौर ऊर्जा किसानों की समृद्धि, महिलाओं की सुविधा, बच्चों की शिक्षा और आदिवासी समाज के विकास का आधार बने।’

पिछले दो वर्षों में क्रेडा ने जिस गति से कार्य किया है, उसने छत्तीसगढ़ को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान दी है। सौर सुजला योजना छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लेकर आई है। राज्य में अब तक लगभग 1 लाख 63 हजार 667 सोलर कृषि पंपस्थापित किए जा चुके हैं। इससे लगभग 1 लाख 96 हजार 400 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है।

पिछले दो वर्षों में हमने लगभग 13 हजार से अधिक नए सोलर कृषि पंप स्थापित किए हैं, जिससे करीब 15 हजार 836 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित हो सकी है। मेरे लिए यह केवल कृषि विकास नहीं बल्कि किसान

“

छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के एक छोटे से गांव में जब पहली बार सोलर हाई मास्ट की रोशनी जली, तो वह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी। वह वर्षों के अंधकार, अलगाव और विकास की प्रतीक्षा पर विजय की कहानी थी। उस रोशनी के नीचे खेलते बच्चों की मुस्कान और पहली बार सुरक्षित महसूस करते ग्रामीणों की आंखों में चमक – यही वह दृश्य है, जिसे क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सक्ती छत्तीसगढ़ के विकास की असली तस्वीर मानते हैं।

”

की आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। सक्ती इस बदलाव को किसान की आत्मनिर्भरता से जोड़ते हैं।

‘जब किसान अपनी सिंचाई व्यवस्था खुद नियंत्रित करता है, तब उसकी खेती केवल उत्पादन नहीं रहती, बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाती है।’

पानी की तलाश से सम्मान की यात्रा तक

ग्रामीण जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है पेयजल की उपलब्धता। सोलर पेयजल योजना के तहत हजारों गांवों में लगाए गए सोलर पंपों ने महिलाओं और बच्चों की दिनचर्या बदल दी है। भूपेंद्र सक्ती इस बदलाव को भावुक होकर याद करते हैं – *‘जब किसी गांव की महिलाएं कहती हैं कि अब उन्हें कई किलोमीटर दूर पानी लेने नहीं जाना पड़ता, तो हमें लगता है कि हमारी योजना सफल हुई।’*

अब तक राज्य में लगभग 28 हजार 803 सोलर पेयजल पंपस्थापित किए जा चुके हैं, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हमने 7 हजार 711 सोलर डुअल पंपस्थापित किए हैं, जिनके माध्यम से लगभग 2 लाख 79 हजार 885 परिवारों को घर-घर नल कनेक्शन के जरिए पानी

उपलब्ध कराया गया है।

जहां सड़क नहीं पहुँची-वहाँ रोशनी पहुँची

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के माध्यम से विकास पहुंचाना क्रेडा की सबसे संवेदनशील उपलब्धियों में शामिल है। निर्याद नेह्रानगर योजना के तहत हमने बस्तर संभाग के 405 ग्रामों में सौर ऊर्जा



आधारित विकास कार्य शुरू किए हैं। अब तक लगभग 7 हजार 498 ऑफग्रीड सोलर प्लांटस्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 22 हजार 549 किलोवॉट है। इससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बस्तर संभाग के कई गांव ऐसे थे जहां आजादी के दशकों बाद भी बिजली नहीं पहुंच सकी थी। सक्ती बताते हैं –

‘जब लिखतगौर और टेकलगुड़ा जैसे गांवों में पहली बार सौर ऊर्जा से टीवी और प्रकाश व्यवस्था शुरू हुई, तो वहां के लोगों ने इसे केवल सुविधा नहीं बल्कि मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर माना।’ यह पहल केवल सुविधा प्रदान करता नहीं बल्कि लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है। जब दूरस्थ क्षेत्रों के लोग सूचना और शिक्षा से जुड़ते हैं, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। उनकी आवाज में गर्व से ज्यादा जिम्मेदारी का भाव दिखाई देता है।

ऊर्जा से सुरक्षा और सामाजिक विश्वास

सोलर हाई मास्ट योजना ने राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नई सुरक्षा भावना पैदा की है। रात के अंधेरे में जो रास्ते भय का प्रतीक थे, वे अब सुरक्षित आवागमन के मार्ग बन रहे हैं। सक्ती मानते हैं कि – *‘रोशनी केवल दृश्यता नहीं देती, वह समाज में विश्वास भी पैदा करती है।’* राज्य में अब तक लगभग 7 हजार 700 से अधिक सोलर हाई मास्टस्थापित किए जा चुके हैं। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रात्रि आवागमन सुरक्षित हुआ है। कई

स्थानों पर दुर्घटनाओं और अपराधों में कमी देखने को मिली है।

प्रकृति और विकास के बीच संतुलन

ऊर्जा विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी उनकी सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत लगभग 60 हजार से अधिक बायोगैस संयंत्रस्थापित किए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हुआ है और जंगलों पर दबाव कम हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण का संयुक्त मॉडल मानते हैं। वे कहते हैं – *‘विकास तभी टिकाऊ होता है जब वह प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले।’*

ऊर्जा आत्मनिर्भरता का सपना

क्रेडा अब शहरी क्षेत्रों में सोलर रूफटॉप और ऊर्जा संरक्षण मॉडल को बढ़ावा दे रहा है। आवासीय सोसाइटियों में सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करने की नई पहल शुरू की है। लगभग 200 सोसाइटियों में कार्य प्रगति पर है और कई स्थानों पर सहमति प्राप्त हो चुकी है। सक्ती इसे भविष्य की ऊर्जा संस्कृति बताते हैं। उनके अनुसार –

‘आने वाला समय ऊर्जा आत्मनिर्भरता का होगा। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का मॉडल राज्य बने।’

नेतृत्व जो योजनाओं से आगे सोचता है

भूपेंद्र सक्ती का नेतृत्व प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक संवेदनशीलता का संतुलन दिखाई देता है। वे योजनाओं को फाइलों और आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में देखने का बात करते हैं।

उनकी सोच का सार उनके एक वाक्य में दिखाई देता है –

‘जब गांव का बच्चा रोशनी में पढ़ता है और किसान अपने खेत में आत्मविश्वास से खड़ा होता है, तब हमें लगता है कि हम सही दिशा में हैं।’

एक रोशनी जो भविष्य लिख रही है

क्रेडा की दो वर्षों की उपलब्धियां दर्शाती हैं कि अक्षय ऊर्जा केवल तकनीकी विकास नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का मजबूत माध्यम बन सकती है। भूपेंद्र सक्ती के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ इस भाषा को समझने और उसे जमीन पर उतारने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज राज्य के गांवों में जलती हर सौर रोशनी केवल बिजली नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भविष्य की नई कहानी लिख रही है।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य तंत्र में दो ऐसे मुद्दे उभरकर सामने आए हैं, जो सीधे तौर पर जनता और छात्रों के भविष्य से जुड़े हैं। पहला—बच्चों को दी जाने वाली एल्वेंडाजोल जैसी दवा, जो कुपोषण और कृमि संक्रमण से बचाती है, अमानक पाई गई। रायपुर और बलौदाबाजार के जिला अस्पतालों में इसका वितरण हुआ।



दूसरा—शासकीय मेडिकल कॉलेजों की PG सीटों को लेकर विवाद, जहां हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नीति निर्माण और क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल दो साल के उनके कार्यकाल में आखिर क्या हो रहा है। लगता है, छत्तीसगढ़ में अमानक दवाओं का सिलसिला अब किसी अपवाद का नहीं, बल्कि एक स्थायी व्यवस्था का रूप ले चुका है और ऐसा सिस्टम तब बनता है, जब ऊपर बैठे लोग या तो अक्षम होते हैं या मौन साझेदार। सबसे शर्मनाक तथ्य यह है कि यह सब कुछ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की नाक के नीचे हो रहा है। मंचों से स्वास्थ्य सुधार के भारी-भरकम भाषण, और जमीन पर बच्चों तक को दी जा रही अमानक दवाएँ—यह विरोधाभास नहीं, यह प्रशासनिक विफलता की खुली स्वीकारोक्ति है मंत्रीजी।

जायसवाल जी जब मंचों से 'स्वास्थ्य सुधार' की बातें करते हैं, तो जमीन पर बच्चे अमानक एल्वेंडाजोल निगल रहे होते हैं। वही एल्वेंडाजोल, जो कुपोषण और कृमि संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए दी जाती है—लेकिन यहाँ वही दवा खुद बीमारी बन चुकी है। मेरा सवाल सीधा है लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के लिए असुविधाजनक हो सकता है— अगर दवा अमानक थी तो खरीदी कैसे हुई?, अगर खरीदी हुई तो जांच में पास कैसे हुई?, अगर पास हुई तो अस्पतालों तक पहुँची कैसे? और अगर अस्पतालों तक पहुँची, तो बच्चों को खिलाई किसके आदेश पर गई? जवाब भी हमें पता है मंत्रीजी क्या दोगे आप, वही हमेशा की तरह 'कार्रवाई की जा रही है।' यही जुमला छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य तंत्र का सबसे घातक वायरस बन चुका है।

मागर प्रश्न तो बनता है न की रायपुर और



दवा में ज़हर-मंत्री मौन

छत्तीसगढ़ में अमानक दवाओं का सिलसिला अब किसी अपवाद का नहीं, बल्कि एक स्थायी व्यवस्था का रूप ले चुका है और ऐसा सिस्टम तब बनता है, जब ऊपर बैठे लोग या तो अक्षम होते हैं या मौन साझेदार। सबसे शर्मनाक तथ्य यह है कि यह सब कुछ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की नाक के नीचे हो रहा है। मंचों से स्वास्थ्य सुधार के भारी-भरकम भाषण, और जमीन पर बच्चों तक को दी जा रही अमानक दवाएँ—यह विरोधाभास नहीं, यह प्रशासनिक विफलता की खुली स्वीकारोक्ति है मंत्रीजी।

बलौदाबाजार के जिला अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में जिस अमानक एल्वेंडाजोल पर अब रोक लगी है, वह रोक पहले क्यों नहीं लगी? क्या बच्चों का शरीर 'टेस्टिंग लैब' है? क्या गरीब का बच्चा इतना सस्ता है कि उस पर दवा नहीं, प्रयोग किए जाएँ? छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस लिमिटेड (CGMSC) हर बार दावा करता है कि दवा खरीदी की प्रक्रिया पारदर्शी है, गुणवत्ता जांची जाती है, मानक पूरे किए जाते हैं। लेकिन जब-जब जांच होती है, मानक पूरे किए जाते हैं। लेकिन जब-जब जांच होती है, CGMSC का यह दावा कागज की तरह फट जाता है। अब यह संस्था गुणवत्ता नियंत्रण की एजेंसी नहीं, बल्कि कमीशन और सेटिंग की मशीन बन चुकी है—बार-बार जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो खुद गवाही दे रहे हैं।

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस लिमिटेड (CGMSC) हर बार यह दावा करती है कि दवाओं की खरीदी पारदर्शी है, गुणवत्ता की जांच होती है, प्रक्रिया सख्त है। लेकिन जमीनी

सच यह है कि CGMSC अब Quality Control Unit नहीं, Commission Control System बन चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और CGMSC अध्यक्ष दीपक मस्के की कथनी और करनी के बीच का फासला इतना गहरा है कि उसमें हज़ारों मरीजों की जान गिर चुकी है—और गिरती जा रही है। शर्मनाक बात यह नहीं कि अमानक दवा पकड़ी गई। सबसे शर्मनाक बात यह है कि किसी का नाम नहीं आता। कौन सी कंपनी थी? किस अधिकारी ने सैंपल पास किया? किसने स्टोर में रिसीव किया? किस CMHO, BMO या फार्मासिस्ट ने वितरण आदेश दिया?

हर बार फाइलें बोलती हैं—और जिम्मेदारी गूंगी हो जाती है। क्योंकि सच्चाई यही है—यह खेल बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं और जब संरक्षण ऊपर से हो, तो नीचे सिर्फ



‘रोक’ लगती है, सज़ा नहीं। वैसे छत्तीसगढ़ राज्य में यह पहली बार नहीं है। छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग पहले भी ऐसे कई ‘अमानक अध्याय’ लिख चुका है—जिनके अंत में हमेशा एक ही पंक्ति जुड़ी रही—
‘जांच के आदेश दे दिए गए हैं।’

- * कुछ वर्ष पहले सरकारी अस्पतालों में स्प्लाई की गई एंटीबायोटिक्स और पेनिकिलर्स अमानक पाई गईं।
- * IV फ्लूइड्स और सलाइन को लेकर भी सवाल उठे—जहाँ मरीजों की हालत बिगड़ने के बाद जांच हुई, उससे पहले नहीं।
- * लैब रीजेंट्स और डायग्नोस्टिक किट्सकी गुणवत्ता पर भी उंगलियां उठीं, जिनसे गलत रिपोर्टें बनने का खतरा सामने आया।
- * कोविड काल में PPE किट, मार्स्क और जरूरी मेडिकल उपकरणोंकी खरीद को लेकर भी पारदर्शिता पर

सवाल खड़े हुए—लेकिन फाइलें आगे नहीं बढ़ीं।

इन घटनाओं को अगर अलग-अलग देखेंगे तो शायद ‘घोटाला’ शब्द भारी लगे। लेकिन अगर इन्हें एक साथ जोड़ दें, तो साफ दिखता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि संस्थागत लापरवाही का सिलसिला है। पैटर्न साफ है—अमानक दवा? खबर? हंगामा? जांच? चुप्पी? अगला टैंडर? अगली अमानक दवा। जनता का विश्वास गिर रहा है और स्वास्थ्य विभाग की साख ICU में पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को अब बताना होगा—क्या विभाग उनके नियंत्रण में है, या अफसर-ठेकेदार गठजोड़ के? आज मामला बच्चों की दवा का है, कल बुजुर्गों की हार्टमेडिसिन का हो सकता है, परसों गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली दवाओं का और तब सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं रहेगा, मौत की जिम्मेदारी तय करने का होगा। अब सवाल अतीत का नहीं,

भविष्य का है, क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताएंगे कि— दवा अमानक मामलों में किस कंपनी ने क्या किया, और किस अधिकारी ने क्या नहीं किया?

अब बात करते हैं मेडिकल PG सीटों के विवाद को। राज्य कोटे की 50% सीटें सुरक्षित की गईं, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटें अब बाहरी छात्रों के लिए खोल दी गई हैं। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार को मजबूरन राजपत्र में संशोधन करना पड़ा। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की PG सीटें, बाहरी छात्रों के लिए खुले दरवाजे, 25 साल में पहली बार PG दाखिले के लिए तीसरी काउंसलिंग करानी पड़ रही है—हर फैसले में नीति की नहीं, नीयत की धुंध दिखती है। मंत्री जी, PG सीटों का विवाद सिर्फ शिक्षा का मामला नहीं, यह छत्तीसगढ़ी युवाओं के भविष्य और अधिकारों का संघर्ष है।

क्या यह नीति छत्तीसगढ़ी छात्रों के अधिकारों के खिलाफ नहीं है?, क्या यह निर्णय लांबी दबाव में लिया गया, या छात्रों के हित में था? मंत्रीजी, मेडिकल छात्रों का आरोप है कि निजी कॉलेज अवैध शुल्क और शर्तें लगा रहे हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग इस पर कार्रवाई करेगा? या यह सब भी सिस्टम की चुप्पीके तहत जारी रहेगा? मंत्री जी, क्या इस बात का जवाब देंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय मरीजों की जान बचाने के लिए चल रहा है, या अमानक दवा स्प्लायर्स को मोटी कमाई कराने के लिए? और अगर जवाब नहीं आया, तो अगली अमानक दवा फिर आएगी—कोई बच्चा फिर चुपचाप जूहर निगल लेगा। मंत्री जी मंच से ‘स्वास्थ्य सुधार’ पर भाषण देंगे और हम पूछेंगे वह सुधार है या संगठित अपराध?





तिरंगा, वक्फ और मुस्लिम समाज

छत्तीसगढ़ में इन दिनों वक्फ बोर्ड, मस्जिदों पर तिरंगा और मुस्लिम समाज के सामाजिक-शैक्षणिक विकास को लेकर एक नई बहस शुरू हुई है। यह बहस केवल धार्मिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि पहचान, राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता के जटिल सवालों को भी छू रही है। इन सवालों के केंद्र में हैं छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज, जिनके कई बयान चर्चाओं और विवादों का विषय बने। लाइफ बर्सिटी के संपादक डॉ. नरेन्द्र पाण्डेय ने डॉ. सलीम राज से इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। प्रस्तुत है इस विस्तृत संवाद के प्रमुख अंश—

भरिजनों में तिरंगा फहराना क्या धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करता?

बिल्कुल नहीं। हम किसी धार्मिक परंपरा को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। नमाज़, कुरान या धार्मिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह केवल राष्ट्रीय सम्मान का विषय है। हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। हमारा उद्देश्य मुस्लिम युवाओं में स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। आर्थिक रूप से कमजोर संस्थानों को सीमित अनुदान देने की योजना भी इसी सोच का हिस्सा है।

भगवाकरणा का आरोप

मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ। भारत की संस्कृति विविधताओं से भरी हुई है। यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएँ सदियों से समाज को जोड़ती रही हैं। भगवा रंग को गलत

तरीके से देखा गया है, जबकि यह त्याग और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जैसे कई उदाहरण हैं, जहाँ साझा सांस्कृतिक परंपराएँ दिखाई देती हैं। हमारा उद्देश्य किसी संस्कृति को थोपना नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और भाईचारे को मजबूत करना है। मस्जिद इबादत की जगह है। वहाँ धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग समाज में गलत संदेश देता है, इसलिए इस पर संतुलन जरूरी है।

वंदे मातरम् और राष्ट्रगान पर विवाद क्यों होता है?

वंदे मातरम् का अर्थ है — मैं तुझे सलाम। इसमें समस्या क्या है? राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। वंदे मातरम् का अर्थ मातृभूमि के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। दुर्भाग्य से राजनीति इन विषयों को विवाद का रूप दे देती है। समाज में डर और अविश्वास पैदा करना किसी भी तरह से सकारात्मक नहीं है। हमें राष्ट्रीय एकाता को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए।

वक्फ संपत्तियों पर कब्जे को लेकर अक्सर विवाद होते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या है?

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास लगभग 7 हजार एकड़ भूमि है और उसमें लगभग 95 प्रतिशत पर कब्जा है। ये संपत्तियाँ ऐतिहासिक दान से मिली हैं। कोई भी जमीन मनमाने तरीके से वक्फ घोषित नहीं की जा सकती। पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है — रजिस्ट्री, आवेदन, कलेक्टर का आदेश, और फिर वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज होती है। आज वक्फ बोर्ड की आय पाँच लाख रुपये भी नहीं है, जबकि यह पाँच करोड़ रुपये तक हो सकती है। कई प्रभावशाली लोगों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। इससे गरीब मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा।

नया वक्फ बिल मुस्लिम समाज को किस तरह प्रभावित करेगा?

नया वक्फ बिल मुस्लिम समाज को तर्कों के लिए लाया गया है। इससे वक्फ की आय बढ़ेगी और उस आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, विधवा



रव्वाजा गरीब नवाज मोईनुद्दीन चिरती की दरगाह में भगवा चादर चढ़ती है। वहाँ केसरिया चावल का प्रसाद बनता है और नॉनवेज प्रसाद नहीं चढ़ता। यह हिंदुस्तान की साझा संस्कृति का अद्भुत दृश्य है। जिसे आम भाषा में भगवा कट्टा जाता है, उसे अर्द्ध-अरबी में चिरितया रंग कहा जाता है।

■ डॉ. सलीम राज

चेयरमैन, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड

और तलाकशुदा महिलाओं की सहायता और गरीब मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई में किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि वक्फ संपत्तियाँ समाज के विकास का माध्यम बनें। वक्फ बोर्ड को केवल धार्मिक संस्था नहीं मानना। यह सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास का माध्यम बन सकता है। अगर वक्फ की संपत्तियों का सही उपयोग हो, तो मुस्लिम समाज आत्मनिर्भर बन सकता है।

संवाद का रास्ता या टकराव की राजनीति?

डॉ. सलीम राज के विचार स्पष्ट रूप से परंपरा और राष्ट्रवाद के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश दिखाते हैं। उनके बयान जहाँ समर्थकों को सामाजिक समरसता की दिशा में प्रयास लगते हैं, वहीं आलोचकों के लिए यह बहस और प्रश्नों का विषय है। लेकिन इतना तय है कि वक्फ, तिरंगा और मुस्लिम समाज के भविष्य पर यह चर्चा अब सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। समाज किस दिशा में जाएगा—टकराव की राजनीति की ओर या संवाद और सुधार की ओर—यह आने वाला समय तय करेगा।



Bhopender Singh,
Director -
AI, Webority
Technologies

8 मार्च को हम 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' मनाते हैं- एक ऐसा दिन जो महिलाओं के संघर्ष, सफलता और उनकी अदम्य शक्ति को समर्पित है। लेकिन इस वर्ष, यह उत्सव केवल उपलब्धियों को याद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की ओर देखने का भी अवसर है। आज के इस 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) के युग में, तकनीक केवल पुरुषों का कार्यक्षेत्र नहीं रह गई है। चाहे आप एक गृहणी हों, उद्यमी हों, कामकाजी महिला हों या छात्रा - AI आपके सपनों को पंख देने के लिए एक 'डिजिटल साथी' के रूप में तैयार है।

1. कामकाजी महिलाएं: कार्य-जीवन संतुलन का मंत्र

ऑफिस की जिम्मेदारियों और घर के बीच तालमेल बिठाना अक्सर तनावपूर्ण होता है। AI यहाँ आपको उत्पादकता को दोगुना कर सकता है।

■ **स्मार्ट असिस्टेंस:** AI टूलस की मदद से आप मिनटों में ईमेल ड्राफ्ट कर सकती हैं, मीटिंग्स के नोट्स बना सकती हैं और अपना पूरा कैलेंडर मैनेज कर सकती हैं।

■ **कौशल विकास-** करियर में आगे बढ़ने के लिए नई स्किल सीखना अब आसान है। AI आधारित प्लेटफॉर्मस आपकी पसंद और समय के अनुसार आपको बेस्ट कोर्सेज सुझाते हैं।

2. महिला उद्यमी: छोटे व्यापार को बनाएं वैश्विक

अगर आप अपना छोटा व्यवसाय चलाती हैं, तो AI आपका 'मार्केटिंग हेड' बन सकता है।

■ **सोशल मीडिया और विज्ञापन:** AI की मदद से आप अपने उत्पादों के लिए शानदार विज्ञापन, आकर्षक पोस्ट और वीडियो कंटेंट मिनटों में तैयार कर सकती हैं।

■ **ग्राहक सेवा:** छोटे व्यवसायों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना मुश्किल होता है, लेकिन 'AI चैटबॉट्स' आपकी अनुपस्थिति में भी ग्राहकों के सवालों के जवाब दे सकते हैं।

3. ग्रहणीयों- घर का स्मार्ट प्रबंधन

घर का प्रबंधन किसी कंपनी चलाने से कम नहीं है। AI इस प्रबंधन को और अधिक आधुनिक बना सकता है।

■ **बजट और योजना:** AI ऐस आपके मासिक



नारी शक्ति और AI: प्रगति का नया डिजिटल युग

खर्चों का विश्लेषण कर बचत के तरीके बता सकते हैं।

■ **सीखने के नए अवसर:** यदि आप कुकिंग, पेंटिंग या कोई नई भाषा सीखना चाहती हैं, तो AI आपके लिए पर्सनल कोच की तरह काम करता है। साथ ही, बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए AI एक बेहतरीन रिसोर्स है।

4. छात्राएं: भविष्य की लीडर्स

शिक्षा के क्षेत्र में AI एक क्रांति है। छात्राओं के लिए यह केवल जानकारी का स्रोत नहीं, बल्कि करियर की दिशा तय करने वाला मार्गदर्शक है।

■ **करियर गाइडेंस:** 'मैं आगे क्या बनूँ?' इस सवाल का जवाब AI आपकी रुचियों और वर्तमान मार्केट डिमांड को देखकर दे सकता है।

■ **प्रोजेक्ट और रिसर्च:** जटिल विषयों को सरलता से समझने और बड़े प्रोजेक्ट्स पर डेटा इकट्ठा करने के लिए AI टूलस समय की बचत करते हैं, जिससे आप रचनात्मकता पर अधिक ध्यान दे पाती हैं।

■ AI फॉर एवरिगन: आपकी प्रगति के डिजिटल टूलस

तकनीक को आजमाना अब बहुत आसान है। यहाँ कुछ मुफ्त AI टूलस हैं जिन्हें आप आज ही शुरू कर सकती हैं-

■ **ChatGPT / Google Gemini:** जानकारी पाने, मुश्किल ईमेल लिखने, बच्चों को पढ़ाने या बिजनेस के लिए नए आइडियाज सोचने के लिए इनका उपयोग करें।

■ **Canva (Magic Studio):** अगर आप अपना छोटा बिजनेस चलाती हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो बिना डिजाइनिंग सीखे शानदार पोस्ट और वीडियो बनाएं।

■ **Perplexity AI:** अगर आप किसी विषय पर गहराई से रिसर्च करना चाहती हैं, तो यह आपको इंटरनेट से सटीक और विश्वसनीय जानकारी खोज कर देता है।

■ **Grammarly:** अपनी अंग्रेजी और राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए यह एक शानदार टूल है।

सुरक्षा और जागरूकता: सबसे जरूरी कदम

एक AI विशेषज्ञ होने के नाते, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि तकनीक का उपयोग करते समय डिजिटल सुरक्षा सर्वोपरि है। महिलाओं को अपनी गोपनीयता के प्रति सजग रहना चाहिए। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी निजी जानकारी साझा करने से पहले ऐप की विश्वसनीयता जरूर जाँचें।

AI केवल एक प्रोग्राम नहीं है, यह एक अवसर है- असमानता को खारिज को पाटने का। यह महिलाओं को समय की आजादी देता है, उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करता है और उनकी रचनात्मकता को एक नई पहचान देता है।

इस महिला दिवस पर, आइए हम संकल्प लें कि हम तकनीक से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे अपनाकर खुद को और अपने समुदाय को सशक्त बनाएंगे। याद रखिए, जब एक महिला शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम होती है, तो पूरा समाज प्रगति करता है।

नंबर, रैंक और तुलना के बीच सिमटती बचपन की दुनिया



अनामिका पाण्डेय

आज का बचपन पहले जैसा नहीं रहा। कभी पतंग, मैदान और दोस्तों की हंसी से भरा रहने वाला बचपन अब नंबर, रैंक और प्रतिस्पर्धा के बोझ तले दबता जा रहा है। सफलता की अंधी दौड़ में बच्चे केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि अपनी भावनाएँ, इच्छाएँ और मानसिक संतुलन भी खोते जा रहे हैं। देश में हजारों बच्चे ऐसे प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन चुके हैं, जहाँ सपनों से ज्यादा अपेक्षाएँ भारी पड़ती हैं। पढ़ाई और करियर की तैयारी के बीच कई बच्चे मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। कई बार यह दबाव इतना बढ़ जाता है कि बच्चे अपने संघर्ष को शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर पाते।

अंकों की होड़ और बढ़ता मानसिक दबाव

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े इस गंभीर संकट की पुष्टि करते हैं। वर्ष 2023 में 13,892 बच्चों ने आत्महत्या की, जिनमें अधिकांश छात्र थे। यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं, बल्कि उन परिवारों की टूटती उम्मीदों और समाज की असफलताओं का आईना है।

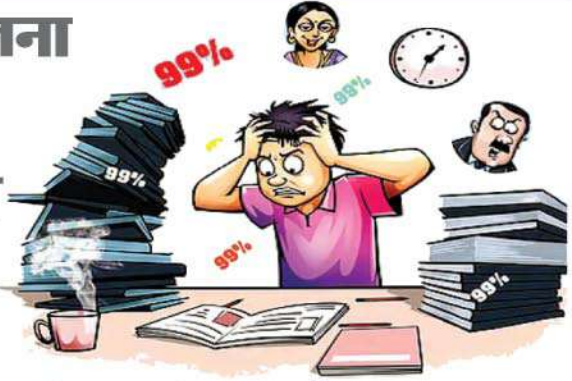
रिपोर्ट बताती है कि लगभग 65 प्रतिशत मामलों में पढ़ाई का दबाव और पारिवारिक अपेक्षाएँ प्रमुख कारण बने। बच्चों की जिंदगी अब केवल परीक्षा के परिणाम और करियर की संभावनाओं तक सीमित होती जा रही है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रतिस्पर्धा का यह माहौल बच्चों के आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित कर रहा है। लगातार तुलना और असफलता का भय बच्चों को भीतर ही भीतर तोड़ देता है।

स्वतंत्रता संकेत दे रहे बढ़ते आंकड़े

पिछले एक दशक में बच्चों और छात्रों में आत्महत्या के मामलों में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2023 के बीच यह संख्या लगभग 65 प्रतिशत तक बढ़ी है। आज स्थिति यह है कि भारत में लगभग हर घंटे एक छात्र आत्महत्या कर रहा है। परीक्षा का दबाव, करियर को लेकर असुरक्षा और सामाजिक अपेक्षाएँ बच्चों के मानसिक संतुलन को कमजोर कर रही हैं।

बारहवाँ और कॉलेज स्तर के छात्रों में यह दबाव और अधिक दिखाई देता है, जहाँ भविष्य को लेकर अनिश्चितता और प्रतिस्पर्धा का तनाव बच्चों को मानसिक रूप से अकेला कर देता है।



सामाजिक संरचना और भावनात्मक दूरी

बढ़ते आत्महत्या मामलों के पीछे केवल शैक्षणिक दबाव ही जिम्मेदार नहीं है। सामाजिक और पारिवारिक संरचना में बदलाव भी एक बड़ा कारण बनकर सामने आया है।

आज कई बच्चे अपनी परेशानियाँ खुलकर साझा नहीं कर पाते। अभिभावकों की उम्मीदें, सोशल मीडिया की आभासी सफलता और समाज की तुलना की संस्कृति बच्चों को एक ऐसे मानसिक दायरे में कैद कर देती है, जहाँ वे खुद को असफल मानने लगते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि भावनात्मक सहयोग और संवाद की आवश्यकता है। जब परिवार और स्कूल बच्चों की भावनाओं को समझने में असफल होते हैं, तब बच्चे मानसिक अवसाद का शिकार हो जाते हैं।

जागरूकता और समाधान की जरूरत

सरकार और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूल और कॉलेज स्तर पर काउंसलिंग और परामर्श सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सरकारी योजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं। बच्चों के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण तैयार करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। शिक्षकों और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, हर बच्चा अलग सपना लेकर जन्म लेता है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था अक्सर उसे एक ही पैमाने पर मापने लगती है। बच्चों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करना बेहद जरूरी है।

आज सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और पारिवारिक अपेक्षाओं ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित किया है। बच्चों को अपनी बात खुलकर कहने का अवसर देना और उन्हें भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना आत्महत्या को घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

बचपन को बचाने की जरूरत

यह समय केवल शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाने का नहीं, बल्कि समाज के आत्ममंथन का है। सफलता की परिभाषा को बदलना होगा। बच्चों को केवल अंक और रैंक से नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा, भावनाओं और व्यक्तित्व से पहचानने की जरूरत है। अगर बचपन को प्रतिस्पर्धा की इस अंधी दौड़ से नहीं बचाया गया, तो आने वाली पीढ़ी केवल सफल पेशेवर तो बन सकती है, लेकिन मानसिक रूप से संतुलित और खुशहाल ईंसान नहीं। बचपन को सुरक्षित रखना केवल परिवार या स्कूल की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि जब कोई बच्चा हारता है, तब केवल एक जीवन नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाएँ भी हार जाती हैं।

परीक्षा
2026



नंबरों से आगे, बच्चों के भविष्य की असली कहानी



संजीत सोनी

छत्तीसगढ़ में जब परीक्षाएँ शुरू होती हैं, तब सिर्फ स्कूलों के कमरे नहीं बदलते—पूरा माहौल बदल जाता है।

सुबह जल्दी उठते बच्चे, देर रात तक जलती लाइटें, माता-पिता

की चिन्तित नज़रें और शिक्षकों की अपेक्षाएँ—सब मिलकर एक सवाल खड़ा करते हैं—

क्या परीक्षा सिर्फ बच्चों की होती है, या पूरे समाज की?

लाइफवर्सिटी मानती है कि परीक्षा केवल प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिका का खेल नहीं है। यह बच्चों के आत्मविकास, परिवार के सहयोग और समाज की सोच की असली परीक्षा होती है।

परीक्षार्थी—जिन पर सबसे ज्यादा दबाव, सबसे कम आवाज

हर बच्चा अलग है—कोई गणित में तेज है, कोई कला में, कोई सवाल पूछने में माहिर है, तो कोई चुपचाप सीखता है।

लेकिन परीक्षा के समय सबको एक ही तराजू पर तौल दिया जाता है—नंबरों के तराजू पर।

प्यारे बच्चों,

अगर तुम्हारे नंबर कम भी आएँ, तो याद रखना—तुम्हारी सोच, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी कोशिशें किसी मार्कशीट में नहीं समा सकतीं। छत्तीसगढ़ की मिट्टी ने मेहनत से इतिहास बनाया है, और तुम उसी परंपरा का भविष्य हो।

माता-पिता: अनजाने में बनता दबाव

अक्सर माता-पिता यह सोचते हैं कि सख्ती बच्चों को बेहतर बनाएगी।

लेकिन तुलना, ताने और 'इस बार तो' जैसे वाक्य बच्चों के भीतर डर भर देते हैं।

लाइफवर्सिटी का साफ मानना है—

'बच्चों को डाँट नहीं, दिशा चाहिए।'

'नंबर नहीं, नज़र चाहिए।'

एक भरोसे भरा हाथ, एक वाक्य—'कोशिश ही सबसे बड़ी जीत है'—बच्चे को टूटने से बचा सकता है।

शिक्षक—सिर्फ परीक्षक नहीं, पथ-प्रदर्शक के रूप में

वह कड़ी हैं जो परीक्षा को डर से सीख में बदल सकते हैं।

जब शिक्षक यह सिखाते हैं कि गलती असफलता नहीं, सुधार की शुरुआत है—तब बच्चा खुलकर आगे बढ़ता है।

आज स्कूल के शिक्षकों के कंधों पर केवल पाठ्यक्रम नहीं, पूरा भविष्य टिका हुआ है।

परीक्षा और मानसिक स्वास्थ्य: अनदेखा सब

परीक्षा के दौरान तनाव, घबराहट और आत्म-संदेह तेजी से बढ़ते हैं।

नींद की कमी, मोबाइल की लत और बातचीत का अभाव बच्चों को अंदर से कमजोर कर देता है।

समय पर बातचीत, थोड़ी छूट और यह भरोसा कि

'तू जैसा है, वैसा ही कीमती है'

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दवा है।

परीक्षा जरूरी है, लेकिन बच्चे उससे कहीं ज्यादा जरूरी हैं।

नंबर रास्ता दिखा सकते हैं, मंज़िल नहीं तय करते।

आज के बच्चों में हुनर है, हिम्मत है और आगे बढ़ने की ताकत है—जूरत है तो सिर्फ एक ऐसे माहौल की, जहाँ डर नहीं, विश्वास हो।

इस परीक्षा मौसम में, आइए बच्चों से सवाल नहीं—साथ पूछें—'तुम ठीक हो?'

स्तन कैंसर से जंग स्वामोशी तोड़ने का समय



प्रो.अंजू सिंह
(ब्रेस्ट ओकोप्लास्टी
सर्जन एवं
फिशागोप्यस्य सर्जरी),
पं. जवाहरलाल
नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज,
रायपुर (छग)

कभी-कभी आँकड़े सिर्फ संख्या नहीं होते, वे समाज की चुप्पी का आईना होते हैं। और स्तन कैंसर से जुड़े आँकड़े भारत की उसी चुप्पी की दर्दनाक कहानी कहते हैं। भारत में महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसरस्तन कैंसर (ब्रेस्ट कैंसर) है। यह एक गंभीर लेकिन समझने और समय पर पहचानने वाली बीमारी है। आँकड़े बताते हैं कि भारत में हर 4 मिनट में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है और हर 8 मिनट में एक महिला की इस बीमारी से मौत हो जाती है। अनुमान है कि वर्ष 2035 तक भारत में कैंसर का बोझ 1.5 गुना बढ़कर 17 लाख से अधिक हो जाएगा। जरा ठहरकर सोचिए, जब आप यह कॉलम पढ़ रहे हैं, तब शायद देश के किसी कोने में किसी घर का दरवाजा खुला होगा, रिपोर्ट हाथ में होगी, और एक परिवार की दुनिया अचानक बदल गई होगी।

बीमारी से ज्यादा खतरनाक – हमारी मानसिकता

सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर का पता अक्सर देर से चलता है। कई महिलाएँ शर्म, डर या जानकारी की कमी के कारण डॉक्टर के पास जाने में देर कर देती हैं। जब तक बीमारी का पता चलता है, तब तक

वह गंभीर अवस्था में पहुँच जाती है। यही कारण है कि भारत में कैंसर से ठीक होने की दर पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम है।

स्तन कैंसर केवल शरीर की बीमारी नहीं है, यह हमारे सामाजिक व्यवहार की भी परीक्षा है। भारत में स्तन कैंसर से जुड़ी सबसे बड़ी त्रासदी बीमारी नहीं, बल्कि संकोच, डर और अज्ञान है। हमारे समाज में महिलाओं को बचपन से सिखाया जाता है—'दर्द सहना है, चुप रहना है, घर संभालना है।' और यही संस्कार कई बार बीमारी को चुपचाप बढ़ने देते हैं। महिला अक्सर अपनी तकलीफ को परिवार की जिम्मेदारियों के पीछे छिपा देती है। परिणाम, जब तक अस्पताल पहुँचती है, बीमारी तीसरे या चौथे चरण में पहुँच चुकी होती है। यही वजह है कि जहाँ पश्चिमी देशों में कैंसर से लड़ाई समय रहते शुरू हो जाती है, वहीं भारत में लड़ाई अक्सर तब शुरू होती है जब बीमारी आधी जीत हासिल कर चुकी होती है।

चिकित्सा की प्रगति, लेकिन पहुँच का संकट

आज चिकित्सा विज्ञान ने चमत्कार किए हैं। ब्रेस्ट ऑनकोप्लास्टी, टार्गेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, लिंकिड बायोप्सी—ये शब्द केवल मेडिकल टर्म नहीं हैं, बल्कि हजारों महिलाओं के लिए उम्मीद की नई खिड़की हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि भारत के कई हिस्सों में आज भी कैंसर का मतलब इलाज नहीं, बल्कि किस्मत मान लिया जाता है।

कैंसर – बीमारी नहीं, सामाजिक संवाद का विषय

कैंसर का इलाज केवल डॉक्टर नहीं करते, इसमें परिवार, समाज और सरकार—तीनों की भूमिका होती है। परिवार को समझना होगा कि महिला केवल जिम्मेदारियों की मशीन नहीं है। उसे अपने स्वास्थ्य के लिए समय और सम्मान दोनों चाहिए। समाज को यह स्वीकार करना होगा कि शरीर से जुड़ी बीमारियाँ शर्म का विषय नहीं होतीं और सरकार को यह समझना होगा कि स्वास्थ्य योजनाएँ केवल घोषणा नहीं, बल्कि जीवन बचाने का संकल्प होती हैं।

स्तन कैंसर से लड़ाई अस्पताल से पहले घर से शुरू होती है। माँ अपनी बेटी से इस विषय पर बात करे, पति अपनी पत्नी को स्वास्थ्य जांच के लिए प्रेरित करे, समाज महिलाओं को यह भरोसा दे कि बीमारी कमजोरी नहीं होती।

बीमारी को नहीं, समय को हराना है

4 फरवरी – विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य केवल बीमारी के बारे में बताना नहीं, बल्कि समग्र देखभाल और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस की थीम है—'United for Unique' इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि हम कैंसर से लड़ने के लिए एकजुट हों। इसका अर्थ यह भी है कि हम हर मरीज को एक आँकड़ा नहीं, बल्कि एक इंसान समझें। हर मरीज की कहानी अलग होती है। किसी के लिए यह बीमारी आर्थिक संकट बन जाती है किसी के लिए मानसिक संघर्ष और किसी के लिए सामाजिक अलगाव। इलाज केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का भी होना चाहिए। स्तन कैंसर को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। लेकिन मृत्यु को रोका जा सकता है और इसका सबसे बड़ा हथियार है समय पर पहचान।

महिलाएँ यहीने में एक बार स्वयं स्तन की जांच करें

- ★ अगर स्तन में गाँठ, दर्द, सूजन, त्वचा में बदलाव या निम्पल से असामान्य स्राव दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
 - ★ 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को नियमित जांच करवानी चाहिए।
 - ★ परिवार में कैंसर का इतिहास हो तो विशेष सावधानी रखें।
- पश्चिमी देशों ने 1980 के दशक में ही जागरूकता अभियान शुरू कर दिए थे। लगभग दो दशक बाद वहाँ मृत्यु दर कम होने लगी। भारत ने 2017 में स्तन कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन नीति और ज़मीन के बीच की दूरी आज भी बनी हुई है। कई शहरों में महिलाएँ आज भी यह नहीं जानतीं कि स्वयं स्तन परीक्षण कैसे किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह विषय अब भी संकोच की दीवार के पीछे कैद है।



फाल्गुन में ना खाए चना



वसंत की आहट के साथ जब फाल्गुन मास आता है, खेतों में पीली सरसों लहराती है, हवा में मादकता घुलती है, तो प्रकृति ही नहीं, शरीर की आंतरिक लय भी बदलने लगती है। और भीतर कहीं एक नई ऊर्जा जागती है। लेकिन आयुर्वेद और नाड़ी विज्ञान हमें याद दिलाते हैं कि यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है।

फाल्गुन आते ही हवा का मिजाज बदल जाता है। न पूरी ठंड, न पूरी गर्मी। दिन में हल्की गरमाहट और रात में ठंडी हवा। अगर इस समय हम अपनी दिनचर्या और खाने की आदतें नहीं बदलते, तो सर्दी-जुकाम, एलर्जी, गला खराब होना, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएँ तेजी से बढ़ सकती हैं।

आयुर्वेद के अनुसार फाल्गुन में शरीर में पित्त का प्रभाव बढ़ने लगता है, जबकि कफ का शमन प्रारंभ होता है। अर्थात् शरीर में गरमी बढ़ाने वाला तत्व सक्रिय होने लगता है और ठंड के दिनों में जो कफ जमा हुआ था, वह अब पिघलकर गले और छाती को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से इस मौसम में जुकाम और एलर्जी ज्यादा देखने को मिलती है। यही कारण है कि इस समय सर्दी-जुकाम, एलर्जी, त्वचा विकार और पाचन संबंधी समस्याएँ उभर सकती हैं। यदि आहार संतुलित न हो तो यह संक्रमणों को भी निमंत्रण दे सकता है।

नाड़ी विज्ञान के अनुसार भी ऋतु परिवर्तन के समय शरीर की नाड़ियों में प्रवाह बदलता है। इड़ा और पिंगला के संतुलन में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। यदि हम भारी, गरिष्ठ और शुष्क भोजन लेते हैं तो यह संतुलन और अधिक बिगड़ सकता है। परिणामस्वरूप शरीर में जड़ता,

थकान और अम्लता बढ़ सकती है। इसलिए इस समय हल्का, ताजा और आसानी से पचने वाला भोजन लेना जरूरी है।

फाल्गुन में चना क्यों ना खाए ?

चना पौष्टिक है, इसमें प्रोटीन भरपूर होता है। लेकिन हर मौसम में हर चीज़ एक जैसी असर नहीं करती। हर ऋतु में हर आहार अनुकूल नहीं होता। चना भारी और शुष्क प्रकृति का होता है - यह वातवर्धक है। इसे पचाने में समय लगता है। ज्यादा खाने से गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। फाल्गुन में पाचन अग्नि स्थिर नहीं रहती, ऐसे में चना अपच का कारण बन सकता है। बढ़ते पित्त के साथ यह एसिडिटी और कुछ लोगों में जलन या त्वचा को परेशानी भी बढ़ सकता है। इसलिए आयुर्वेद इस मास में चने के सीमित या त्याग की सलाह देता है, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें पहले से गैस, एसिडिटी या त्वचा संबंधी समस्या हो।

फाल्गुन के सुपरफूड-बेर और अंगूर

प्रकृति हर मौसम में वही फल देती है, जिसकी हमें जरूरत होती है। जहाँ कुछ आहार त्याग योग्य हैं, वहीं कुछ इस ऋतु के लिए वरदान समान हैं। बेर शरीर को हल्की ठंडक देता है, खून साफ रखने में मदद करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और अंगूर पेट साफ रखने में सहायक, शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, एसिडिटी कम करने में मददगार है। ये दोनों फल-

- बढ़ते पित्त को संतुलित करते हैं। शरीर को ठंडक देते हैं
- त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। रक्त को शुद्ध करते हैं

- कब्ज और अम्लता में राहत देते हैं। पाचन सुधारते हैं
 - रोग-प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करते हैं। मौसमी रोगों से रक्षा करते हैं
- बिना दवा के शरीर को संतुलित करते हैं। प्राकृतिक औषधि की तरह कार्य करते हैं
- बेर विशेष रूप से कफ और पित्त दोनों को संतुलित करता है, जबकि अंगूर शरीर में नमी और ऊर्जा का संचार करता है। ये दोनों फल ऋतु के अनुरूप प्रकृति का उपहार हैं।

ऋतु अनुसार आहार - स्वस्थ शरीर

आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है-'ऋतुचर्या'। अर्थात्, मौसम के अनुसार आहार और व्यवहार। यदि हम प्रकृति के नियमों के साथ चलें, तो शरीर स्वयं संतुलित रहता है। फाल्गुन में हल्का, ताजा और सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। मूंग दाल, हरी सब्जियाँ, सूप, छाछ और मौसमी फल इस समय लाभकारी होते हैं। सुबह जल्दी उठकर योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम कफ को संतुलित करता है और पित्त को नियंत्रित रखता है।

तया करें, तया न करें ?

- सुबह थोड़ा जल्दी उठें
- हल्की एक्सरसाइज या योग करें
- गुनगुना पानी पिएं
- ताजा और घर का बना खाना खाएं
- बहुत ज्यादा तला-भुना और जंक फूड कम करें
- दिन में ज्यादा देर तक सोने से बचें

त्योहारों का मौमजा, सेहत का भी ध्यान

फाल्गुन यानी महाशिवरात्रि और होली का महीना। मिठाइयाँ, पकवान और रंगों का उत्साह। लेकिन ध्यान रखें-त्योहार का आनंद तभी है जब सेहत साथ रहे। मीठा और तला-भुना सीमित मात्रा में लें। रंग खेलने से पहले त्वचा पर हल्का तेल लगाएं। ज्यादा ठंडी चीजें खाने से बचें। पानी पर्याप्त पिएं।

फाल्गुन हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ चलना ही असली समझदारी है। अगर हम समय पर अपनी आदतें बदल लें, तो छोटी बीमारियों से बच सकते हैं और बिना दवा के भी स्वस्थ रह सकते हैं।

मौसम बदल रहा है—अब आपकी थाली भी बदलिए। ताजी फाल्गुन का उत्साह और वसंत की ताजगी सच में महसूस होगी। प्रकृति हर मौसम में हमें संकेत देती है—बस आवश्यकता है उन्हें सुनने और अपनाने की। फाल्गुन हमें यही संदेश देता है कि संतुलन ही स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मंत्र है।



फाल्गुन में प्रेम

अनामिका पाण्डेय

फाल्गुन की एक शाम थी।
हवा में हल्की गर्माहट घुलने लगी थी और कॉलेज कैम्पस के किनारे खड़ा पलाश का पेड़ लाल फूलों से भर गया था।

आदित्य उसी पेड़ के नीचे बैठा था, और सामने वैदेही खड़ी थी।
दोनों चुप थे।

शायद शब्द कम पड़ गए थे, या भावनाएँ ज्यादा हो गई थीं।
आदित्य और वैदेही को कहानी किसी फिल्म जैसी शुरू हुई थी।

लाइब्रेरी में नोट्स मांगने से लेकर कॉफी डेट तक, फिर देर रात फोन कॉल्स और 'हम हमेशा साथ रहेंगे' वाले वादे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से सब बदल गया था।

आदित्य को वैदेही की बातों पहले जैसी अच्छी नहीं लगती थीं। वैदेही को लगता था कि आदित्य कहीं दूर चला गया है जहाँले ही वो उसके सामने बैठा हो।

वैदेही ने धीरे से पूछा—
'तुम बदल गए हो आदित्य?'
आदित्य ने सिर झुका लिया।

हवा का एक झोंका आया, पलाश के कुछ फूल टूटकर उनके बीच गिर गए।

आदित्य बोला—
'मुझे नहीं पता वैदेही 'बस' ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है। सब कुछ होते हुए भी, कुछ खाली—सा लग रहा है।'

वैदेही की आँखों में हल्की नमी उतर आई।
इस मौसम में जहाँ हर चीज़ ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उनके रिश्ते में एक अजीब-

सी बेचैनी थी।

आदित्य को नए लोगों से बात करने में उत्साह महसूस होने लगा था।

लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद वैदेही अब उसकी 'स्टोरी' का हिस्सा नहीं रही।
और वैदेही

वो बस उसे खोने के डर से चुप हो गई थी।
उस शाम आदित्य ने हिम्मत करके कहा—
'शायद, हमें थोड़ा स्पेस लेना चाहिए।'
वैदेही ने कुछ सेकंड तक उसे देखा।

फिर धीरे से मुस्कुराई, वैसी मुस्कान, जसमें दर्द छुपा हो।

उसने कहा—'अगर तुम्हें लगता है कि स्पेस से तुम खुद को समझ पाओगे, तो ले लो।
मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं'

यह सुनकर आदित्य को पहली बार महसूस हुआ कि कभी-कभी प्यार पकड़कर रखने में नहीं, छोड़ देने में भी होता है।

कुछ दिन बाद,
आदित्य अकेले घूमते हुए उसी पलाश के पेड़ के पास फिर आया।

उसने देखा— पेड़ से पुराने सूखे पत्ते गिर रहे थे और उसी शाखा पर नई कोपलें भी निकल रही थीं।

उसे अचानक अपने पुराने शिक्षक की कही बात याद आई—

'प्रकृति जब बदलती है तो वह कुछ तोड़ती नहीं, बस धीरे-धीरे नया बना देती है।'
आदित्य को एहसास हुआ—

वो वैदेही से दूर नहीं हो रहा था, वो अपने भीतर चल रहे बदलाव से घबरा रहा था।
उसे नया चाहिए था, लेकिन नया पाने के

लिए पुराने को खत्म करना जरूरी नहीं होता।

आदित्य ने उसी रात वैदेही को मैसेज किया— 'क्या हम मिल सकते हैं? ब्रेकअप के लिए नहीं, समझने के लिए।'

वैदेही आई
और इस बार दोनों ने कोई वादा नहीं किया।
बस एक बात तय की—

'हम एक-दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हम साथ-साथ बदलना सीखेंगे।'

उस शाम दोनों उसी पलाश के पेड़ के नीचे बैठे थे।

हवा में अब भी वही गर्माहट थी, लेकिन उनके मन में बेचैनी नहीं थी।

वैदेही ने धीरे से कहा— 'शायद प्यार का मतलब हमेशा एक जैसा रहना नहीं होता।'

आदित्य मुस्कुराया और बोला— 'हाँ, शायद प्यार का मतलब साथ बदलना होता है।'
मगर याद रखिये

फाल्गुन रंगों का महीना है, लेकिन हर रंग पका नहीं होता।

मन उड़ना चाहता है उसको उड़ने दीजिए—
पर रिमोट अपने विवेक के हाथ में रखिए।

दोस्तों, फाल्गुन लाइफ में चेंज लाने का सिमल देता है, लेकिन चेंज धीरे और सौच समझकर करना चाहिए।

जैसे मौसम धीरे बदलता है, वैसे ही लाइफ भी धीरे बदलनी चाहिए।

खिला-खिला मधुवन



कोयल की मीठी तान, भ्रमर सुनाए गान,
झूम-झूम नाचे तरु,
'सुषमा' संसार है।
श्याम पीत रंग धारे, फूलों पर वारे-न्यारे,
सरराम गाते प्यारे,
ध्वनि का प्रसार है।
जीवन को प्राण देते, कष्ट सभी हर लेते,
प्रकृति का उपहार,
ईश्वर का प्यार है।
खिला-खिला मधुवन, हरित-हरित वन,
विविध रंगों से सजे,
सौंदर्य अपार है।

सुषमा प्रेम पटेल (रायपुर छ.ग.)

आध्यात्म के दरबार में हैसियत

नरेन्द्र षण्डेय

में एक दृश्य देखकर लौटा हूँ और बोल रहा हूँ।

यह कोई कोई खबर नहीं है, बस एक अनुभव है। मेरे शहर में एक संत का आगमन हुआ। कहा गया—काफ़ी पहुँचे हुए हैं। दुर्लभ सिद्धियाँ, दीर्घ साधना, मौन की गहराई और दृष्टि की तीक्ष्णता, सब कुछ था उनके पास।

आगमन किसी संन्यासी की सहज यात्रा नहीं था, उनका आगमन किसी साधारण निमंत्रण पर नहीं हुआ था, बल्कि शहर के एक प्रतिष्ठित घराने के आग्रह पर हुआ था। निवेदन—जो आज के समय में शब्द कम, व्यवस्था ज्यादा होता है। वही घराने, जिनके नाम शहर के नक्शे से ज्यादा, फ़ाइलों और फ़ैसलों में चलते हैं।

शहर के मध्य कार्यक्रम रखा गया। मंच पर राजनीति थी, कुर्सियों पर व्यवसायी थे, और आगे की पंक्तियों में समाजसेवी— जिनके नाम के आगे 'सेवा' और पीछे 'प्रभाव' जुड़ा रहता है।

संत ने व्याख्यान दिया। समाज हित की बातें कहीं। हृदयवर्तों दीं—कैसे जीवन जिया जाए, कैसे लोभ से दूर रहा जाए, कैसे अहंकार त्यागा जाए। संत बोले— नैतिकता पर। संस्कारों पर। भटकते समय पर। लोग सिर हिलाते रहे—कुछ श्रद्धा में, कुछ सहमति में और कुछ कैमरे की तरफ़ देखते हुए।

अगले दिन का कार्यक्रम थोड़ा अलग था। मेल-मुलाकात। शिष्य के निवास पर। लाजबंद व्यंजन—जिन्हें देखकर उपवास भी टूट जाए। वही चेहरे, वही बड़े नाम, वही प्रभावशाली उपस्थिति। राजनीति, उद्योग, सामाजिक प्रतिष्ठ।

संत जो से एक-एक कर परिचय कराया जा रहा था—

'ये बड़े उद्योगपति हैं,'

'ये सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी हैं,'

'ये राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं'

हर व्यक्ति की पहचान उसके पद, पैकेज और प्रभाव से हो रही थी।

मैं एक किनारे खड़ा था। शांत। अदृश्य। न नोटिस हुआ, न परिचय। क्योंकि न मैं व्यवसायी हूँ, न राजनीतिक, न नामजदा समाजसेवी। मेरे पास परिचय के लिए सिर्फ़ एक चीज़ थी—जिज्ञासा। और जिज्ञासा, इस तरह के आयोजनों में कोई योग्यता नहीं मानी जाती।

मैं लौट आया। बिना शिकायत के। बिना क्रोध के। बस एक सवाल साथ लेकर— क्या



“

मेटालिस्टिक लोग भाव नहीं देते। और अध्यात्म के दरबार में भाव से पहले हैसियत पूछ ली जाती है। अध्यात्म की राह समझ से परे लगती है, और उसे समझाने वाले गुरु अक्सर पहुँच से बाहर होते हैं।

”

यही संत के शब्दों की अंतिम सच्चाई है? सोचता रहा— आध्यात्म आखिर है क्या? दिशा देता है या सुविधा खोजता है?

Urgent और Important को समझने का दावा करता है,

लेकिन अक्सर भीड़ की प्राथमिकताओं में उलझ जाता है।

सोचने लगा— संत के शब्दों की सच्चाई क्या है? उनको दिशा क्या है? क्या अध्यात्म आज भी वही है, या अब उसे भी नेटवर्क और नेमप्लेट चाहिए?

तभी एक और विचार आया— आज समय है आध्यात्म को आधुनिकता के साथ लेकर चलने का—लेकिन आधुनिकता पूरी तरह Materialistic है। और जो इस मेटालिस्टिक दुनिया में सबसे ज्यादा डूबा है, उसे ही शायद आध्यात्म को सबसे ज्यादा ज़रूरत है।

पर यहाँ एक अजीब विरोधाभास है— आध्यात्म कहता है—छोड़ दो, तो मिलेगा। और मेटालिस्टिक ध्योरी कहती है—पाने के लिए

भी अध्यात्म ज़रूरी है।

यानी दोनों ही एक-दूसरे को साधन बना रहे हैं। तो फिर छोड़े कौन? और पाए कौन? मैं इसी द्वंद में खड़ा एक मध्यमवर्गीय हूँ।

हम इतने मेटालिस्टिक नहीं हो पाते कि सत्ता और संत—दोनों को साध सकें। और इतना अध्यात्मिक नहीं हो पाते कि सब छोड़ सकें।

हम न पूरी तरह मेटालिस्टिक हो पाते हैं, कि संत हमें पहचानें और न पूरी तरह अध्यात्मिक हो पाते हैं, कि संसार हमें समझे। हमारे लिए गुरु तक पहुँचना कठिन है। और जो पहुँच गए हैं, उन तक पहुँचने का रास्ता अक्सर पैसे, पहचान और प्रभाव से होकर जाता है।

मेटालिस्टिक लोग भाव नहीं देते। और अध्यात्म के दरबार में भाव से पहले हैसियत पूछ ली जाती है। अध्यात्म की राह समझ से परे लगती है, और उसे समझाने वाले गुरु अक्सर पहुँच से बाहर होते हैं।

शायद यही कारण है कि आज भी सबसे बड़ा अध्यात्म किसी मंच पर नहीं, किसी आयोजन में नहीं, किसी सिद्ध पुरुष के परिचय में नहीं— बल्कि उस प्रश्न में है, जो चुपचाप लौटते हुए मन के भीतर उठता है और शायद उसी प्रश्न से सच्ची यात्रा शुरू होती है कि अध्यात्म मंच पर है, लेकिन जिनसे दूर और जीवन भाग रहा है, लेकिन दिशा के बिना।

मैं अब भी उसी सवाल के साथ खड़ा हूँ—कि क्या अध्यात्म छोड़ने की कला है, या पाने का साधन?

मन का युद्ध भूमि

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥



गतांक से आगे

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिअग्रयः।

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥

‘आप (गुरु द्रोण), भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त (भृश्रिवा) – ये सब मेरी सेना के श्रेष्ठ योद्धा हैं।’

यहाँ सबसे पहले गुरु को संबोधित करता है ‘भवान्’ यानी आप –सीधा, स्पष्ट और एकदम प्रथम स्थान पर। यह सम्मान नहीं, बल्कि स्मरण के माध्यम से बंधन है। वह गुरु को याद दिलाता है कि ‘आप मेरे साथ हैं’ –

यानि अब आपकी जिम्मेदारी है, आपका विकल्प नहीं। उन्हे मानसिक रूप से बांध दिया जाता है। और गुरु अब केवल ‘सैनिक’ नहीं, आरोग्य की तरह जिम्मेदार हो जाते हैं। यह आधुनिक भाषा में वही ‘emotional blackmail leadership’ है – जहाँ व्यक्ति किसी रिश्ते को ‘कर्तव्य’ बनाकर बांध लेता है, भले ही भावनात्मक विश्वास न हो।

अब गौर कीजिए –

कर्ण – उसका सबसे प्रिय, निष्ठावान मित्र – फिर भी उसके नाम में न सम्मान है, न गौरव। यह बताता है कि दुर्योधन के मन में भीष्म और कर्ण के बीच की आंतरिक टकराव पहले से बैठी है।

वह जानता है कि कर्ण युद्ध में अब तक सक्रिय नहीं हो सकता, इसलिए उसका नाम बस Formal Mention बन गया है। यह भाव तब आता है जब रिश्ते में अनकही दूरी या छिपी निराशा होती है।

और हमें पता है – कर्ण उस समय तक युद्ध का मुख्य सेनापति नहीं है, क्योंकि भीष्म ने साफ़ कह दिया था – ‘जहाँ तक मैं जीवित हूँ, कर्ण युद्ध में भाग नहीं ले सकता।’ इसलिए यह छुपी हुई असहमति का भाव है। ‘अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ति’ इन

यही वह भाव है जब लीडर अपनी टीम को ‘tools’ की तरह देखता है, ‘trust’ की तरह नहीं। पर उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं होता। यहाँ दुर्योधन दिखा रहा है कि उसकी सेना में वीर हैं, पर उनके लिए उसका मन अंदर से निश्चित या गौरवान्वित नहीं है। यह दर्शाता है कि दुर्योधन की अपनी सेना के साथ emotional bonding कमजोर है।

तीन नामों में भी कोई विशेषण नहीं है। ये नाम बिना विशेषणों के आते हैं – मानो वह बस ‘गिनती’ पूरी कर रहा हो। यही वह भाव है जब लीडर अपनी टीम को ‘tools’ की तरह देखता है, ‘trust’ की तरह नहीं। पर उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं होता। यहाँ दुर्योधन दिखा रहा है कि उसकी सेना में वीर हैं, पर उनके लिए उसका मन अंदर से निश्चित या गौरवान्वित नहीं है। यह दर्शाता है कि दुर्योधन की अपनी सेना के साथ emotional bonding कमजोर है। वह अपने योद्धाओं को ‘support system’ नहीं, बल्कि ‘tool set’ की तरह देख रहा है।

आज की कॉर्पोरेट दुनिया में मान लीजिए कोई CEO कहे- ‘आप हैं – मेरे Chief Strategy Officer। फिर हैं CFO, HR Head, और Product Manager... और, हाँ, मार्केटिंग हेड भी।’ यह युनकर Marketing Head को कैसा लगेगा? ‘बस नाम भर लिया, क्या मैं कोई भीड़ का हिस्सा हूँ?’

श्लोक 9-

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः।

भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥

आप सब योद्धा, अपनी-अपनी जगहों पर स्थित रहकर, हमारे सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह की रक्षा करें। केवल भीष्म की रक्षा!

अब यह बड़ा दिलचस्प है – सेना लाखों की, युद्ध असीम है, पर दुर्योधन सब योद्धाओं को कहता है- ‘भीष्म की रक्षा करो।’ यह सिर्फ़ आदेश नहीं है – यह स्वीकारोक्ति है। कि ‘मेरी सेना की रीढ़ केवल भीष्म हैं – अगर वो टूटे, तो हम बिखर जाएंगे।’ यानी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, और वह पहले ही ‘रक्षा’ की बात करने लगा।

(शेष अगले अंक में)



सौर ऊर्जा से सशक्त छत्तीसगढ़... आत्मनिर्भरता की ओर - क्रेडा के साथ...



क्रेडा के 02 वर्षों की सुनहरी उपलब्धियां

सौर सुजला योजना

राज्य के किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत राज्य शासन द्वारा रियायती दरों पर सोलर पम्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना से किसान साल भर सिंचाई करने में सक्षम हो रहे हैं, साथ ही कई फसल लेने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।



प्रदेश में अब तक कुल 1,65,081 सोलर पम्प की स्थापना सौर सुजला योजना अंतर्गत की जा चुकी है, जिससे 1,98,097 (हैक्टेयर) सिंचित हो रही है।

विगत 02 वर्षों की उपलब्धियां

उपलब्धि (नग)
14,611

सिंचित रकबा (हैक्टेयर)
17,532

सोलर हाई मास्ट

क्रेडा द्वारा राज्य के ग्रामों, कस्बों, निकायों, शहरों के मुख्य चौराहों / सार्वजनिक स्थलों में प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिकोण से सोलर हाई मास्ट संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। इससे रात्रिकालीन आबागमन सुरक्षित हो रहा है। इन संयंत्रों की स्थापना से अंधकार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं एवं अपराधों में कमी लाई जा सकती है। इस योजनांतर्गत कुल 7767 नग सोलर हाईमास्ट की स्थापना की जा चुकी है, जिसकी कुल क्षमता 7662.13 किलोवाट है।



विगत 02 वर्षों की उपलब्धियां

उपलब्धि (नग)
1927 नग

क्षमता
2312.4 किलोवाट

सोलर पेयजल योजना



पहूँचविहीन ग्राम जहाँ विद्युत प्रदाय न होने के कारण पम्प की स्थापना किया जाना संभव नहीं था, ऐसे स्थलों में क्रेडा द्वारा सोलर हैंड पम्प की स्थापना की गई है। सोलर पम्प (ऊँचाई 6 मीटर) से ग्रामवासियों को 24 घंटे जल उपलब्ध हो जाता है तथा उन्हें पानी लाने हेतु दूर नहीं जाना पड़ता। वर्तमान में जल जीवन मिशन अंतर्गत अधिकांश संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। इस योजनांतर्गत कुल 28,995 नग सोलर पेयजल पंप की स्थापना की जा चुकी है, जिससे 6.98 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

विगत 02 वर्षों की उपलब्धियां

उपलब्धि (नग)
8099

लाभान्वित परिवार
2.61 लाख

ऑफग्रीड सोलर पॉवर प्लांट

प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों, आश्रमों / छात्रावासों, शालाओं, पुलिस थानों, शासकीय भवनों, धरनु, व्यवसायिक परिसर, संस्थागत तथा सामुदायिक स्थलों में ऑफग्रीड रूपटॉप संयंत्रों की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।



सौर संयंत्रों की स्थापना से न सिर्फ प्रकाश व्यवस्था की जा रही है बल्कि ऊर्जा संरक्षण भी किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत कुल 7,519 नग सोलर ऑफग्रीड पॉवर प्लांट की स्थापना की जा चुकी है, जिसकी कुल क्षमता 22607 किलोवाट है।

विगत 02 वर्षों की उपलब्धियां

उपलब्धि (नग)
624 नग

क्षमता
1740 किलोवाट



नियद नेल्ला नार योजना योजना का प्रारंभिक वर्ष -2024-25

नियद नेल्ला नार योजना (आपका अच्छा गांव योजना) अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के माओवाद प्रभावित वनरत संभामा के सार्वजनिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राज्य सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इस योजनांतर्गत जिला सुकमा, बीजापुर, कांगेर, देतेवाड़ा एवं नारायणपुर में आयोजित 71 केंद्रों में सम्मिलित 405 ग्रामों में विभागीय योजनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार क्रियान्वयन किये जाने संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

- नियद नेल्ला नार योजनांतर्गत जिला नारायणपुर के विकासखण्ड ओरछा के घोर नवरतल प्रभावित क्षेत्र के ग्राम मसपुर, मेटानार में आजादी के बाद पहली बार सोलर हाईमास्ट के माध्यम से रोशनी पहुंची है।
- आजादी के 78 साल बाद पहली बार जिला सुकमा के रिलगेर, टेकलगुडा व पूवर्ती जैसे अर्यंत नवरतल प्रभावित एवं विकास में पिछड़े ग्रामों के सामुदायिक स्थलों / भवनों में सौर ऊर्जा से संचालित 02-02 नग टी वी और डी टी एच प्रदान कर उनका संचालन किया जा रहा है।



कार्य का नाम	स्थापित संयंत्रों की संख्या	प्रगतिरत संयंत्रों की संख्या
• कुपकों को सोलर पम्प (सिंचाई)	415	08
• सोलर हाई मास्ट संयंत्र	131	12
• सोलर ड्यूल / पेयजल पम्प	625	40
योग	1171	60



प्रगतिशील युवा विकसित छत्तीसगढ़

खेल प्रोत्साहन योजना लागू, ओलंपिक विजेताओं के लिए **₹1-3 करोड़** का पुरस्कार और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल ढांचे का विकास



सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, लगभग **32,000** पदों पर भर्ती



नवा रायपुर में क्रिकेट अकादमी की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को **7.96 एकड़** भूमि आवंटित



160 आईटीआई को मॉडल संस्थान में बदलने हेतु **₹484 करोड़** स्वीकृत



राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए **उद्यम क्रांति** योजना



34 नगरीय निकायों में "नॉलेज बेसड सोसाइटी" हेतु **लाइट हाउस** निर्माण की पहल



छात्रों को QR कोड के जरिए



डिजिटल संकेतन करें

www.dprcg.gov.in

Facebook: /ChhattisgarhCMO
Twitter: /DPRChhattisgarh
Website: www.dprcg.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री